MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(1) The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Bill, 1993.

(2) The Salary, Allowances and Pension of Parliament Members of Parliament (Amendment) Bill, 1993.

(3) The Central Laws (Extension to Arunachal Pradesh) Bill, 1993.

(4) The Tezpur Uunversity Bill, 1993.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Employment of Manual Scavangers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Bill, 1993, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th May, 1993."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1993, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th May, 1993."

(III)

"In accordance with the provisions of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 13th May, 1993, agreed without any amendment to the Central Laws (Extension to Arunachal Pradesh) Bill, 1993, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 28th April, 1993."

(IV)

"In accordance with the provisions of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 13th May, 1993, agreed without any amendment to the Central Laws (Extenendment to the Tezpur University Bill, 1993, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 29th April, 1993."

Madam, I lay a copy of each of the Bills, "The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Bill, 1993" and "The Salary, Allowances and Pension of Members (Amendment) Bill, 1993" on the Table.

Discussion on the Working of the Ministry of Industry—Contd.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उद्योग मंत्रालय की कार्यावलि के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। हम से पहले दो पूर्वतन वक्ताओं ने, दो माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से काफी आंकड़ों के ऊपर आधारित अपना बयान दिया है। मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहती क्योंकि वे सारे सरकारी आंकड़े हैं। मोटी-मोटी अपनी बात, अपने दल का दृष्टिकोण आपके सामने, सदन के सामने और माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी।

उद्योग हम क्यों लगाते हैं? इसका आधार क्या है? हम उद्योग इसलिए लगाते हैं कि देश की तरक्की हो, अपने देश में आम जनता की जरूरी चीजें जो हैं, कृषिजन्य उत्पादन के अलावा जीवनयापन के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों का हम उत्पादन कर सकें। साथ ही इसके लिए पैसा भी चाहिए, आमदनी भी चाहिए देश को और व्यक्ति को। व्यापार बढ़ाने के लिए हम लोग उद्योग लगाते हैं। यह तो उद्योग नीति का मोटा-मोटा आधार है। हमारे

देश में क्या हुआ कि पिछली सदी में उद्योग लगाया गया इस देश में और वह धीरे-धीरे बढ़ता गया। आजादी के बाद जो उद्योग नीति आई उसमें हमारे देश में यह कहा गया कि अगर हम मिश्रित उद्योग चलायें, मिश्रित अर्थनीति चलायें तो हमारा देश जल्दी तरक्की करेगा। वही पुरानी चलती रही अभी तक और ठीक ही चल रही थी। लेकिन अचानक इस वर्तमान सरकार ने उस अर्थ नीति को, उस उद्योग नीति को बदल दिया जिसे हम नई उद्योग नीति कहते हैं। उसमें पुरानी जो मान्यतायें थीं, पुरानी जो परम्परायें थीं उनको बदल दिया और यह कहा गया कि अगर हम दुनिया के बाजार में अपना सामान नहीं बेचेंगे, दुनिया के कम्पीटीशन में नहीं जायेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। यह कहा गया कि जो आरक्षण दिये गये उनको उठा लिया जाए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आफ इकोनोमी होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन आफ इंडस्ट्री होनी चाहिए। यह हमारी सरकार ने कहा। लेकिन उसकी उपलब्धि क्या हुई। उनके अपने दल के एक ही सदस्य ने पूरी उनकी बखिया उधेड़ दी। उन्होंने बताया कि उनकी इस उद्योग नीति के बाद, वर्तमान उद्योग नीति के बाद, नई इंडस्ट्रियल पालिसी के बाद सरकार की कितनी विफलता रही इसको एक-एक करके उदाहरण के जरिए बताया है। मैं उन उदाहरणों को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि हमारी उद्योग नीति जो इस देश में अभी तक चलाई गई है वह उद्योग नीति पूरे देश के लिए एक समान नहीं थी, सामाधिक आधार पर वह नीति नहीं चलाई गई। मैं पूर्वांचल की रहने वाली हूं। हमारा प्रांत सबसे अधिक खनिज सम्पदा से भरा पड़ा है। हम खनिज सम्पदा पूरे देश को देते हैं। थरमल पावर के लिए हमारे यहां की खनिज सम्पदा से भारत मालामाल हो रहा है। मेरे से पूर्वतन वक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र बहुत ही विकसित प्रांत है। सही बात है। मैं मानती हूं। उन्होंने पटना का भी कई दफा नाम लिया और कहा कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, पटना पिछड़ा हुआ इलाका है। सही बात है। उन्होंने यह भी कहा कि विल टु वर्क होना चाहिए था। पालिटिकल विल होना था आगे बढ़ने के लिए। वह पालिटिकल विल बिहार में नहीं था, यह बिल्कुल सही बात है। सन् 1952 से जिन लोगों ने शासन चलाया उनमें यह पालिटिकल बिल नहीं था कि अपने प्रांत को बढ़ाते। अपने प्रान्त का विकास किया जाय। लेकिन यह नहीं हुआ आप जानती होंगी कि एक फ्रेट इक्वेलाइजेशन की पालिसी थी। जो रेलवे का सामान दूसरे प्रान्तों में जाएगा, कच्चा माल जितनी दूर जाएगा उतना कम किराया होगा। लेकिन जो कच्चा माल मंगायेंगे उसका किराया कम नहीं होगा। वर्तमान सरकार ने बिहार प्रान्त के लिए उसको बदला, बड़ी जद्दोजहद के बाद बदलना पड़ा। यह तो मैं आपके उत्तर देने के लिए कह रही हूं। लेकिन जरूरी बात यह कहना चाहती हूं कि आज जो उद्योग नीति है उस उद्योग नीति से इस देश का समग्र विकास नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, यह मैं बताना चाहती हूं। आज के जो इनके सरकारी विभाग हैं, इंडस्ट्रियल इंटरपैन्योर मेमोरन्डम है उसमें अगस्त, 1990–92 तक जितने यूनिट्स को मान्यता दी है उसमें नार्दन स्टेट का हुआ है 41.5 परसेंट, वेस्टर्न स्टेट्स का हुआ है 34.4 परसेंट और साउदर्न स्टेट्स का हुआ है 14.4 परसेंट और ईस्टर्न स्टेट्स जो मिनरल रिच हैं, रा-मेटिरियल रिच है, उन ईस्टर्न स्टेट्स का हुआ है 5.6 परसेंट। यह स्थिति नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है जहां से तेल निकलता है, जिससे कच्चा माल निकलता है, कागज के कारखाने के लिए सामान मंगाते हैं, कोयला मंगाते हैं। उनको आपने क्या किया? हमारी सरकार ने इस संबंध में क्या किया है? नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यह सिर्फ 2 परसेंट हुआ है। इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं है।

यह कहा जाता है कि वर्तमान सरकार जब आई, पिछले दिनों जब यह कांग्रेस की सरकार आई है तो इसने कहना शुरू कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर बिल्कुल बीमार हो गये हैं और इनसे देश का

[श्रीमती कमल सिन्हा]

काम चलने वाला नहीं है। कारण यह बताया गया कि जो श्रमिक काम करते हैं वे निखट्टू हैं, वे कामचोर हैं। इसलिए पब्लिक सैक्टर को घाटा हो रहा है। इससे बढ़कर गलतफहमी कुछ नहीं हो सकती है। इस देश के पब्लिक सैक्टर में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसका कारण मिसमेनेजमेंट है। जो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट हैं वे टक्नोक्रेट बन जाते हैं। टक्नोलोजी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वे टक्नोक्रेट की जगह पर बैठ जाते हैं और कारखानों की देखभाल करने लगते हैं। उत्पादन से और जेनरेशन से जिनका कोई मतलब नहीं है वे जेनरेशन में चले जाते हैं। तो घाटा नहीं होगा तो क्या होगा? इन जगहों पर एपाइन्टमेंट सरकार करती है। उसके कारण मिसमेनेजमेंट होता है। खुल्लमखुल्ला लूट होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पब्लिक अन्डरटेकिंग बीमार हो जाते हैं। कुछ तो बीमार लिए गये थे। चूंकि हमारी पालिसी थी कि देश का कल्याण हो तो बीमार उद्योगों को नेशनेलाइजेज किया जाय। अब कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ही इसका इलाज है। निजी उद्योगों को अब तक बढ़ावा नहीं देंगे तब तक कम्पीटीशन होने वाला नहीं है। इसलिए निजी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जो सरकारी उद्योग हैं वे घाटे में चल रहे हैं, ह्वाइट एलीफेन्ट हैं, उन्होंने बहुत पैसा खा लिया है, इसलिए निजी उद्योगों को साधन मुहय्या किये जाये। निजी उद्योग कल कारखाने चलायें।

What is private about these private enterprises?

ये कितने प्राइजेज इन्टरप्राइजेज हैं इनके पास पैसा कहां से आता है? ये सरकारी बैंकों से लोन लेते हैं, पब्लिक मनी से अपना उद्योग चलाते हैं। तो फर्क क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेज सरकारी उद्योगों की देखभाल करते हैं, सरकारी नियंत्रण में चलते हैं। जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनका नियंत्रण बिलकुल निजी हैं। उसमें सरकार का हाथ नहीं है। वर्तमान उद्योग नीति में कहा गया है कि हम निजी उद्योग को छूट देंगे, डिकंट्रोल और डिलायसस करेंगे। इसके उदाहरण सदस्यों ने पढ़ पढ़ कर बताये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं। एम०आर०टी०पी० ऐक्ट में तरह तरह के सुधार किये गये हैं, तरह तरह की सुविधा दी गयी है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में सुविधा दी है, विदेशी सामग्रियों को इम्पोर्ट करने के लिये तरह तरह की सुविधाये दी है। लेकिन सुविधा क्या नहीं दी गयी? मैडम, इस देश के उद्योगों, खासकर जो आम जनता की जरूरत की चीज हैं, ऐसी चीजों को उगाने के लिये, ऐसी चीजों का उत्पादन करने के लिये जो कल-कारखाने इस देश में बनाने चाहिये थे, वह सरकार ने नहीं बनाये। एक तरफ, अगर देश में हम देखें, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी तरफ मीडियम इंडस्ट्री हैं, तीसरी तरफ एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री हैं, उसके बाद स्माल इंडस्ट्री है और उसके बाद सबसे छोटी टिनी इंडस्ट्री है। यह हमारी इंडस्ट्री की पिक्चर है। जो हैवी इंडस्ट्री है उसको कुछ निजी लोग, प्राइवेट उद्योगपति भी चलाते हैं और कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी है जिन्होंने अच्छा काम किया है। उद्योगों के विकास के लिये जो सबसे आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह हमारी सरकार ने नहीं विकसित किया है। सबसे आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिये? सबसे पहले उसके लिये पावर जनरेशन होना चाहिये। बिना पावर के कोई उद्योग नहीं चल सकता है। लेकिन हमारे देश में आज तक समग्र रूप से अगर देखा जाय तो पावर जनरेशन आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ है। जितना पावर जनरेशन उद्योगों को बढ़ाने के लिये चाहिए वह सरकार ने नहीं किया है। जिस काम को सरकार कर सकती थी---सरकार नान-कन्वेंशनल इनर्जी के सोर्स को बढ़ा सकती थी---उसको भी नहीं किया गया। हाइडल पावर के सोर्स को बढ़ा सकती थी, लेकिन वह भी नहीं किया। थर्मल पावर यहां जरूर है। यह देश गर्म देश है। हम यहां सूर्य की रोशनी से भी शक्ति-उत्पादन कर सकते थे लेकिन वह भी नहीं किया गया है। नतीजा यह है कि यह देश उद्योगों को बढ़ाने के मामले में It is a power starved country. हो सकता है कि एक-दो प्रांतों में कुछ

ज्यादा उत्पादन बिजली का हो रहा हो, जैसा महाराष्ट्र में होता होगा, जैसा पंजाब में होता होगा, जैसा गुजरात में होता होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिये, अगर आप रेल गाड़ी से जांय, यहां से लेकर पूर्वांचल में जांय या दक्षिण में जांय या उत्तर में जांय, किसी तरफ भी जांय, इस देश के विकास का चित्र किसी अंधेरी रात में आपको दिख जायेगा। दूर-दूर, मीलों-मील चले जांय उसके बाद कहीं एक टिमटिमाती हुई रोशनी आपको दिखायी देगी। यह हमारे देश के विकास का चित्र है। अंधेरी रात को अगर रेल गाड़ी से आप जांयें, हवाई जहाज से जायेंगे तो नहीं दिखेगा इस देश में सबसे जरुरी था इन्फ्रास्क्टर डेवलप करना और जिसके लिये सबसे आवश्यक था पावर सेक्टर को डेवलप करना लेकिन यह काम नहीं किया गया। रा-मटीरियल सेक्टर को जितना डेवलप करना चाहिये था, आइरन ओर, स्टील, सेलेबल स्टील को---वह भी नहीं किया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम को जितना डेवलप करना चाहिये था वह नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टेशन को जितना डेवलप करना चाहिये था वह नहीं किया गया। नतीजा है कि आज देश के जिस हिस्से में इन्फास्ट्रक्चर आफ इंडस्ट्री को डेवलप किया गया वहां तो डेवलप मेंट हुआ लेकिन जिस हिस्से में इन्फास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ वहां पर विकास का काम नहीं हो पाया, उद्योगों के विकास का काम नहीं हो पाया। महोदया, नतीजा क्या हुआ है? एक तरफ कहीं पर तो विकास का काम हुआ है और कहीं पर देश पिछड़ा हुआ है। आखिरकार इस दिशा हीन विकास से आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? यह जो आपकी नयी औद्योगिक नीति आयी है, मैं तो यहकहूंगी कि यह बिल्कुल दिशाहीन है। यह दिशाहीन औद्योगिक नीति इस देश को कहां ले जाना चाहती है? इस देश मे 15 करोड़ जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी जरुरत की चीजों का उत्पादन कराने की बात हो रही है और उन्हीं के लिये ग्लोबलाइजेशन आफ एकानामी की भी बात हो रही है, उन्हीं को खरीदने के लिये हिन्दुस्तान को हम दुनियां का बाजार बनाना चाहते हैं। हम अपना दरवाजा खोल देना चाहते हैं। हम इम्पोर्ट करेंगे कंज्यूमरिस्ट गुडज़ का, कंज्यूमरिस्ट आर्टिकल्ज़ का। मैंने अभी कल परसों अखबार में पढ़ा इंग्लैंड के बारे में। वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने वहां के उद्योगपतियों से बातचीत की है और कहा है कि हम आपस में मिल जुल कर देखेंगे ताकि यहां के उद्योगों का विकास हो सके और जिन देशों को जरुरत है उन देशों को हम अपना सामान बेचेंगे। इस विषय में उन्होंने यह उदाहरण दिया कि हम हिन्दुस्तान में अपना सामान कैसे बेचेंगे। हमारे देश के लोगों को विदेशी सामान के लिए बड़ी चाहत भी है। हम खुल्लम-खुला प्रचार भी कर रहे हैं पेप्सी कोला से लेकर, कपड़ा मशीनरी, विलास की सामग्री, घरेलु उपयोग की सामग्री, सब विदेशी होनी चाहिये। नतीजा यह हो रहा है हम औजार बनाते जा रहे है। हम जो अपना उत्पादन करते हैं, हमारे देश के उत्पादन का जो हम विदेशों को निर्यात करते हैं वह हम 30 प्रतिशत करते हैं। यह भी छोटे उद्योगों के उत्पादन से निर्यात हम करते हैं। एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री का उत्पादन हम लगभग 40-45 प्रतिशत करते हैं। शेष जिसको सनराइज़ इंडस्ट्री कहते हैं न्यु टेक्नोलोजी के तहत जो डेवलपमेंट हुआ है इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री का उससे उत्पादित सामग्री जो है, उसमें से कुछ निर्यात करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत हेवी इंडस्ट्री का कर लेते हैं जैसे बी०एच०ई० एल० का सामान हम बाहर भेजते हैं। तो चित्र यह है कि हमारे यहां जो कुछ उत्पादन होता है औद्योगिक क्षेत्र का, उसका आधे से ज्यादा छोटे उद्योगों और कृषिजनित उद्योगों से हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिये? क्या हमें केवल विलास की सामग्री का आयात करके फारेन एक्सचेंज को खर्च करना चाहिये या हमारे देश की जो अपनी जरुरत की चीज़ें हैं, उसको हम खुद पूरा करें? हम सेल्फ सफिशियेंट हो जाएं और उसके बाद जो

[श्रीमती कमला सिन्हा]

हमारी जरुरत से ज्यादा है उसको विदेशी बाजारों में बेचें तभी हमारी देश की तरक्की हो सकती है नहीं तो वास्तविक विकास नहीं हो सकता है । हमारी जो वर्तमान उद्योग नीति है, उस उद्योग नीति का सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने नुस्खा दिया कि उद्योग पिछड़ गया है । पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन साहब जो कामर्स मिनिस्टर भी हैं, ने एक फार्मूला बताया, आस्टेरिटी फार्मूला । यह आस्टेरिटी फार्मूला लागू किस-के ऊपर हो, श्रमिकों के ऊपर लागू हो । इस देश में रिसोर्स क्रंच है । उसको दूर करने के लिए हम को कमर कसनी होगी। विदेशों से हमने कर्जा लिया है । हमारा बी०ओ०पी० बढ़ता जा रहा है । इसको दूर करने के लिए हमें आस्टेरिटी ड्राइव लागू करना होगा ? यह आस्टेरिटी ड्राइव क्या है ? इसने सबसे पहले किस पर चोट की ? इस देश के आर्गेनइज्ड सेक्टर में काम करने वले दो करोड़ श्रमिक हैं, सबसे पहले उनके ऊपर इसने चोट की है । डिप्टी चेयरमैन साहब ने सबको बारी-बारी से बुलाया । सभी दलों के लोगों को, ट्रेड यूनियंस के लोगों को चर्चा करने के लिए बुलाया और उनसे चर्चा करने का मेरा भी सौभाग्य हो गया । मैंने उनसे साफ-साफ पूछा था कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है व्हिंग क्लास से तो उन्होंने कुछ बात बताई । अब सवाल यह उठता है कि श्रमिकों का डी०ए० आप फ्रीज कर देंगे, उनका एल० टी० सी० काट देंगे, उनकी सुविधाएं छीन लेंगे और वी०आर०एस० देकर नौकरी से छुट्टी कर देंगे । इंटरनेशनल मोनिटेरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस देश की इकोनोमी की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए । रिस्ट्रक्चरिंग आफ इकोनोमी के तहत यह भी है कि इस देश में काम करने वले लोगों की संख्या अधिक है। काम करने वले लोगों की जो संख्या अधिक है, इसको कम करो, यह हुक्मनामा आया । जिनसे हमने कर्ज लिया, यह हुक्मनामा उनका था जिसके तहत वी०आर०एस० काम काम चालू हो गया । यह कहा गया कि लोगों की संख्या घटानी है तो श्रमिकों, मजदूरों, कामगरों की संख्या को घटाना है । लेकिन उनको कोई चोट नहीं लगे, घटाने से तकलीफ न हो इसलिए एक कुशन हम दे रहे हैं ताकि तुम गिरो तो तुम्हारा सिर न फटे । तो सेफ्टी कुशन्स और सेफ्टी नेट बनाया है । बड़ा अच्छा नाम दिया है नेशनल रिन्यूअल फंड और उसके साथ-साथ कहा है नेशनल रिहैबिलीटेशन फंड । इसमें तीन कैटेगरीज बनायी गयी थी । पिछले साल सेप्टेम्बर महीने में इंडियन लेबर कांफ्रेंस हुई थी । संयोग से मैं उसमें थी । श्रम मंत्री ने एक लम्बा-चौड़ा भाषण दिया, दस्तावेज भी पेश किया और उसमें उन्होंने कहा कि तीन कैटेगरीज में कैसे-कैसे लोगों की छंटनी होगी । 20 से लकर 30 साल की उम्र की एक कैटेगरी, 30 से लेकर 45 साल तक एक कैटेगरी और 45 से ऊपर वालों की एक कैटेगरी । सबसे पहले जाने वाले 45 से ऊपर वाले होंगे । सड़क के हवाले हो जाएंगे और उसके बाद नीचे वाले । तो ये जो नीचे वाले लोग हैं उनको कहा गया कि रिडिप्लायमेंट करने के लिए हम तुम्हें री-ट्रेन करेंगे, जरुरत के मुताबिक री-ट्रेन करेंगे । कहां री-ट्रेन करके आप भेजेंगे ? जरा बताइये मुझे । जरा मंत्री महोदया बता दें । कौन-सी नयी इंडस्ट्रीज इन्होंने खोली हैं ? इंडस्ट्री विभाग ने कौन-कौन से नये उद्योग खोले हैं जहां जो लोग निकले जाएंगे उसके री-डिप्लायमेंट होगा । कौन बैठा हुआ है लेने के लिए । इस तरह की धोखाधड़ी की बात क्यों की जाती है । लोगों को इस तरह का धोखा देने की बात क्यों की जाती है । यह गलत बात क्यों की जाती है ।

यह कहा गया कि हमारे देश की नयी उद्योग नीति के कारण इंडस्ट्रियल एटमोस्फियर में बहुत परिवर्तन आ गया है । इंडस्ट्रियल हेल्थ में बहुत सुधार हो जाएगा । बाहर से मल्टीनेशनल्स हमारे यहां आ रहे हैं और उनको किसी-किसी जगह पर जहां एक्सपोर्ट ओरियंटेड इंडस्ट्री खोले जाएंगे उनमें 100 परसेंट इक्विटी शेयर देने की बात की गयी है । यह फैसला सरकार ने ले लिया है और दूसरे उद्योगों में 51 परसेंट इक्विटी शेयर मिलेगा

मारूति जो सरकारी गाड़ी थी वह अब सरकारी गाड़ी नहीं है वह प्राइवेट गाड़ी हो गयी है । सुजूकी कम्पनी की हो गयी है । 51 परसेंट शेयर हो गया है सुजूकी कम्पनी का । उसका नाम अब मारुति से बदलकर सुजूकी होना चाहिए और इस तरह अनेकों कारखानों के साथ होगा . . .'(व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: नयी गाड़ी को इन्होंने सुजूकी बना दिया है. . . (व्यवधान)

श्रीमती कमला सिन्हा : बहुत अच्छा किया है, कम से कम धोखाधड़ी तो नहीं की है ।

मैं यह कह रही थी कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं इससे किसको धोखा देने की बात की जा रही है । एक तरफ तो 51 परसेंट से लेकर 100 परसेंट इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं । मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं जैसे मल्टी-नेशनल कभी इस देश में नहीं था । इस देश में तो अनेकों मल्टीनेशनल्स शुरु से, आजादी के पिछले से थीं । चूंकि हम अंग्रेजों के दो सौ साल गुलाम रहे हैं इसलिए उन्होंने जो व्यापार चलाया वह आज भी चालू है और फिर दूसरे देशों के लोग भी अमेरिका के लोग भी आए । दूसरे और लोग आए । यूनियन कारबाइड क्या है ? मैं पूछना चाहती हूं कि डनलप क्या है । इसी तरह से दवाओं की कम्पनियां हैं । यह सब क्या है । ठीक है इक्विटी शेयर उनका ज्यादा नहीं था । अब तो हो गया है ।

यह भी कहा गया कि जो एन.आर. आई.ज. नान-रेजीडेंट इंडियंस आएंगे उन हम 100 परसेंट रिपट्रिएशन की सुविधा देंगे अगर वे यहां उद्योग लगाएंगे । मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कितने उद्योग लगे हैं एन.आर.आई.ज. के द्वारा ? बताइये उनकी संख्या ? कौन-कौन क्षेत्र में लगे हैं, यह भी बताइये ? कितनी पूंजी लगी है और कितना रीपट्रिएट होकर चला गया है । मेरे ख्याल से इनकी संख्या बढ़ी नहीं है ।

मल्टीनेशनल्स को देखने का और उनके साथ काम करने का मेरा भी कुछ तजुर्बा है । मल्टीनेशनल्स वहीं पर, किसी भी देश में जब कभी भी जाते हैं यह चीप लेबर के लिए जाते हैं । अपने देश में अमेरिका में, जर्मनी में, योरोप के किसी भी देश में अगर यह कारखाना खोलेंगे इंग्लैंड आदि में तो उनको जो मजदूरी देनी पड़ेगी अपने श्रमिक को उसका दसवां बीसवां या एक हिस्सा यहां देनी पड़ेगी । जो टेक्निकली ट्रेन्ड मजदूर हैं उनको अगर वहां सौ डालर मिलेगा तो हमारे यहां शायद उसे एक सौ भी नहीं मिलेगा । यह तो हिसाब है । इस हालत में . . . (समय की घंटी) मुझे पांच मिनट का समय दीजिए । आपने सबको दया करके लम्बा-लम्बा समय दिया है । कुछ मेरे ऊपर भी मेहरबान हो जाइये । तो मैं यह कह रही थी कि इस तरह से मल्टी-नेशनल को बढ़ावा देना, यह अपने देश के उद्योगों को बेच देने की बात होगी । और तो और मैं तो यह निश्चित रूप से कह सकती हूं कि अपने देश की आर्थिक स्वायत्ता को भी बेचने की बात होगी ।

8.00 p.m.

इकनामिक स्लेवरी आज मैं जानती हूं कि आज दुनिया में कोई पोलिटिकल स्लेवरी होना मुश्किल है । दूसरा विदेशी आकर हमारे ऊपर हुकुमत नहीं करने बैठेगा, लेकिन जिसके हाथ में पैसे की थैली की स्ट्रिंग होगी जिसके हाथ में पैसे की कुंजी होंगी, इंटरनेशनल मानेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डिवैलपमेंट बैंक, यह सारे इस देश की अर्थ नीति को कंट्रोल करेंगे और आर्थिक कंट्रोल जिसके हाथ में गया, हम उसके गुलाम हो गये ।

कल ही यहां पर एक सवाल उठाया गया था, यशवन्त सिन्हा ने उठाया था और लोगों ने कहा था कि हमारे यहां बजट के पहले हमने सलाह ली इंटरनेशनल मानेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से और एशियन डिवैलपमेंट बैंक से कि हम क्या करें, जरा आप हमें बताइये । अब हमारा देश यह सार्वभौम देश है, इस देश की यह नौबत आ गई कि

श्रीमती क ल सिंहा]

हम दूसरे से पूछें कि आप बताइए कि हम किस मद में कितनी अलाग्मेंट करेंगे कितना खर्चा करेंगे और कैसे-कैसे हम अपने देश की इकानमी को चलायेंगे । हर बात में हमें डिक्टेशन लेना, यह बात हम कहां तक ले जाना चाहते हैं ।

एक तरफ गांधी जी थे जिनकी तस्वीर आज भी हर जगह लगी रहती है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वह कहा करते थे ग्राम स्वराज्य हो, हिन्दुस्तान स्वायत्तशासी हो, देश को अपनी जरूरत की चीजों का अपने आप उत्पादन करे, गांव से शहर तक, शहर से लेकर बड़े शहरों तक, ताकि हम स्वावलम्बी हों और आज गांधी जी का नाम बेचने वाली सरकार इस देश को परावलम्बी बना रही है, इस देश की आर्थिक स्वायत्ता को बेच रही है और इस देश के उद्योगों को विदेशियों के हाथ में देना चाहती है । निजी उद्योगपति के साथ-साथ विदेशी उद्योगपति के हाथ में देना चाहती है ।

एन ०आर ०आई० की बात कही गई है । मैंने पूछा था कि कितने एन०आर०आई० इस देश में आये हैं ।

एक बात और—किसी भी देश के उद्योगो के विकास के लिए एक अच्छा एटमासफियर चाहिए, हैल्दी एटमासफियर चाहिए, देश के अंदर ला एंड आर्डर की हालत अच्छी होनी चाहिए । पिछले कुछ दिनों से भारत में ला एंड आर्डर की हालत ऐसी नहीं है, जिससे कोई भी उद्योगपति यहां आकर उद्योग लगाए ।

सुबह घर से निकलो शाम को घर वापिस जाएगा कि नहीं, आदमी का कोई ठिकाना नहीं है उसका, चाहे वह मारूति गाड़ी में जाने वाला क्यों नहीं हो, एयरकंडीशन गाड़ी में जाने वाला क्यों नहीं हो और राह का चलने वाला क्यों नहीं हो । छह दिसम्बर के बाद तो इस देश की हालत इतनी खराब हो गई है ।

Nobody is safe in this country. The health of this country has been degraded like anything. कोई भी विदेशी उद्योगपति इस हालत में यहां पूंजी नहीं लगाएगा, क्योंकि पूंजी लगाने के लिए उनको जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा उनको जो एटमासफियर तैयार करना होगा उत्पादन के लिए, वह एटमासफियर यहां नहीं है ।

भले ही हमारे महाराष्ट्र के भई जितनी भी बात कहें या करें, लेकिन महाराष्ट्र भी इस वक्त मुसीबत का सामना कर रहा है । बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद—

Bombay will no more be the economic Capital of India. Take it from me.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I don't agree with you.

श्रीमती कमला सिन्हा : हालत बहुत खराब होती जा रही है इस देश की और इससे आपको चिंता होगी, हमें भी चिंता है, हम परेशान हैं इसके लिए—हम नहीं चाहते कि यह हालात हो । हम चाहते हैं कि इस देश की हालत सुधरे, इस देश के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति को सुधारा जाए, इस देश के एटमौसफियर को सुधारा जाए, ताकि इस देश का औद्योगिक विकास हो सके ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी । इस देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक है कि छोटे उद्योगों का विकास करना, उसमें लागत, खर्च कम है, उसमें उत्पादन शीघ्र होता है और थोड़ी सी रिसर्च और टैकनालोजी उनको दी जाए, तो वे कैन अचीव वांडर्स । यह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं । आज इस देश में लगभग साढे तीन लाख उद्योग बंद हैं, उनमें लगभग 1200 मझोले उद्योग हैं, कुछ बड़े उद्योग भी बंद हैं, छोटे उद्योगों की संख्या जो बंद पड़े हुए हैं वह अढ़ाई लाख हैं । तो इस तरह से खुलवाओ और बन्द करो, इससे तो काम नहीं चलने वाला है । जिसको खुलवाया जाए, उसको सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए और सारी सुविधायें दी जाएं । और ऐसा एटमोसफियर बने ताकि वह विकास कर सके । हरेक कस्बा में, जहां जो उद्योग हो सकता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी हमारा बेसिक इंडस्ट्रीज है, आज भी इस देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर ही

आश्रित हैं । तो एग्रीकल्चर को, पिछले दिनों यहां मंत्री महोदय कह रहे थे और श्रम मंत्री ने भी कहा था और हमारे कामर्स मंत्री भी कह रहे थे, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा था कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना चाहते हैं । एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डिवेलपमेंट करना चाहते हैं ।

And agriculture sustains the populaton explosion. This is a myth.

मैंने उस दिन भी उनको कहा था, आज भी कह रही हूं इस सदन में, एग्रीकल्चर को आज यह कैपेसिटी नहीं है कि वह इतना पापुलेशन एक्सप्लोजन को और इतने जो नए बाजार में लोग आ रहे हैं जिनकी संख्या आप लोगों ने गिनाया है इस सदी के अंत तक 10 से 12 करोड़ लोग, नौजवान बेकार हो जायेंगे, जो काम के बाजार में आयेंगे और उनको काम नहीं मिलेगा । जब नौजवानों के हाथ में काम नहीं मिलेगा तो वे खुराफात करते हैं आइडल ब्रेन इज डेविल्ज वर्कशाप और वे खुराफात ऐसे करेंगे कि इस देश का विनाश कर डालेंगे । तो इस देश को विनाश से बचाने के लिए ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए उद्योग मंत्रालय को इस पर सोचना चाहिए, आवश्यक हो तो विचार करने के लिए गोष्ठी बुलाएं और विचार करें । इसमें स्माल स्केल इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसके ऊपर हमारा ज्यादा इम्फेसिस होना चाहिए, न कि बड़ी इंडस्ट्री, न कि मल्टी नेशनल, मल्टी नेशनल यहां आयेंगे तो हमारे देश का वह शोषण करेंगे । हमारे देश का विकास नहीं करेंगे और भगवान के लिए, अगर कहीं कहीं भगवान हैं तो भगवान के लिए आप यह कंज्यूमरस्टिक गुड्ज का जो उत्पादन कर रहे हैं, उसको जो छूट दे रहे हैं वह बंद कीजिए । वह हमारे देश के मिजाज के साथ खपता नहीं है । यह इस देश के 15 करोड़ जो पैसे वाले हैं वही इस देश के नहीं हैं, इस देश के वे भी हैं जिनके घर में दो शाम चूल्हा नहीं जलता है, जिसको भोजन नहीं मिलता है, जिसको कपड़ा नहीं मिलता है, वह भी इस देश में रहता है, उसके लिए भी सोचिए । उद्योग का मेन थ्रस्ट उसी के ऊपर होना चाहिए कि अनटूदलास्ट हम जाएं । उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया कराएं । उनकी जरूरत की चीजों को पूरा करें और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें । आज तक उद्योग मंत्रालय ने जो भी कुछ किया है नई इकोनोमिक पालिसी के जरिये यह इस देश के लिए भयंकर खतरे की बात है । अगर इसको तब्दील नहीं किया जाएगा, इसका थ्रस्ट चेंज नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा तो इस देश के आने वाले दिन बहुत ही दुखदायी होंगे ।

महोदय, आपने मुझे 5 मिनट का अधिक समय दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : यह ह उस कब तक चलेगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अभी तो यह चर्चा चालू है । जब तक आप बैठना चाहें तब तक चलेगा । . . (व्यवधान) कल साढ़े नौ बजे हम लोग उठे थे ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Ministery of Industry. I have been hearing with rapt attention the hon. Members from the other side who have said that this Government is directionless, that this Government has no policy on foreign investment. They also said that 45 years of Congress rule ruined the industrial development of the country. Madam, there is no doubt that the industrial policy was envisaged by our great stalwart leader, Pandit Nehru, in the form of a mixed economy having development of industries in the private sector and also in the public sector for generation of employment in this country and for ploughing back the investment that is made in the public sector units for the purpose of develop-mental activity. One thing that the hon. Members sitting on the other side have forgotten—I don't know whether they are trying to conceal the fact—is that the world economic scenario, the industrial aspect, is totally changing. The plan that has been brought by our forefathers for the industrial development of this country needs to be re-examined for the simple reason that no

[Shri V. Narayanasamy]

longer any country which has got a large defence force is considered to be a super-power but a country which has got a strong economic base is considered to be a super-power in the world. Therefore, if India does not follow a new economic policy, a new industrial policy, we will remain as a backward country in the world. India is a developing country. We have to see the new climate which is prevailing in the world arena and we have to frame our policies according to that. When the new Government took over in the year 1991, our hon. Prime Minister and the Finance Minister brought a new economic policy giving a new thrust to the economic situation prevailing in the country. Everybody knew pretty well what the economic situation was in 1990-91, from the middle of 1990, when the previous Government was there. Everybody knew that the industrial development was on the negative side and the balance of payments position was at the lowest ebb and it was at that time that the present Government took over the reins of administration. Then we have to concentrate on agricultural sector, industrial development and infrastructural development. We have to concentrate more on bringing foreign funds for the purpose of developing local industries in the country. I would like to submit—I don't want to quote the figures given by the hon. Members—that the small-scale sector is the core sector as far as the industrial development of this country is concerned. The reason is that a lot of foreign exchange is earned by the sector for this country. The Government has brought a new policy, a novel policy, that is, equity participation of 24 per cent, for the small-scale industries. Secondly, the interest is to be paid of the arrears due to the small-scale industries and a new Bill was brought by the hon. Minister and it was passed by the House. The number of industries was about 18.26 lakhs in 1989-90 and it was increased to 19.38 lakhs in a period of one year. The level of growth was 3.6 per cent in this country. Various items which were in the general sector have been transferred and reserved for the small-scale industries. It was done for the purpose of giving protection to the small-scale industries. More than 836 items have been categorised and given to the small-scale sector for the purpose of developing the smal-scale industries. Organisations like NSIC SSIDC, NABARD, etc., are working for the purpose of developing small-scale industires in this country. As regards the working of these organisations, I have a complaint. I have my personal experience as far as the NSIC is concerned. Some of the CMDs and Chairman, who are working in these organisations which are run for the purpose of developing small-scale sector industries and monitoring, are not taking interest in the development of the small-scale industries in the country. Our country is basically an agriculture-oriented country. There is enormous potential for developing agro-based industries by bringing in new technologies from abroad. The hon. Members from the other side were telling us that we were buying technology from abroad. I have no complaint about it. I welcome the new technology that comes to our country for developing new industries and for developing the industrial base in this country. Then there is a complaint that we are mortgaging our sovereignty for the purpose of getting technology and also funds from abroad. It is a myth. China which is considered to be a closed door country has received foreign investment from the Chinese people abroad for more than 27 million dollars, for the purpose of developing industries. When we get 2 million dollars, there is a hue and cry from the other side that India is mortgaging its sovereignty. There are NRIs abroad who would like to come forward and invest in the industrial sector. We would welcome that. We also welcome foreign investment, even from multinationals in our country. Now, a time has come when our coutry has to

see that there is competition in the industrial sector. Whether it is large-scale industry or medium-scale industry or small-scale industry, we should invite competition and when the multinationals come in it, there will be quality improvement in the production of goods in our country Then definitely our own industries which are getting protection from the Government and through various laws, will improve their efficiency. I just now referred to NSIC and other organisations. The climate in those organisations for the purpoe of giving prototype to the small scale industries and also arranging finances to the small scale industries, is not up to the expectation. The reason is that they are running these organisations in a bureaucratic, manner. It will not be going out of the subject if I say that even the employees working there are not taken care of by the management concerned. Even when the term of the CMDs there is over, they get extension for a further period of three years. This is the state of affairs prevailing in these small scale industries. These organisations should be developed for the purpose of helping the small scale industries.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): Not now. Not during our tenure.

SHRI V. NARAYANASAMY: Whether it was during our the Janata Dal period or any period. I have a complaint about it. (*Interruptions*). I agree with the hon. Minister that it happened during the period of Janata Dal. At the same time I would say that it happened when you were helping the Janata Dal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Mr. Sukomal Sen, please don't interrupt. Mr. Narayanasamy, you address the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: These organisations are not bringing new technology from abroad. They are not developing. Even the incentives that are given to the small scale industries are not being taken care of. Where are these organisations going? They are not able to meet their own expenses. That is the situation under which these organisations are working. How can they help the small scale industries to develop in this country? Madam, the banking sector is also not helping the small scale industries. I raised this matter earlier also. I told the Finance Minister to take care of this fact. I told him to see that the small scale industries which have been running efficiently and which are giving foreign exchange worth more than Rs. 9300 crores to this country are now in a position to survive because the working capital has been stopped by the banks in the name of the securities scam. The JPC was appointed to investigate into the securities scam. Madam, banks are not giving adequate funds to the small scale industries. How can a small scale industry survive in these conditions? It is the duty of the Finance Minister and also the Minister for Small Scale Industries to see that there is proper monitoring and proper advice is given to the banks for the purpose of developing the small scale industries in this country. Madam, now, I want to say something about khadi and village industries which are very wonderful organisations. These were visualised and developed by our great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi for the purpose of making these industries employment-oriented in the rural areas. Our leaders had given a great impetus for developing the khadi and village industries. But now, the sad state of affairs is that they have not only become an organisation for another bureaucratic system but they are also not taking steps to provide employment in the rural areas: This has become substitute organisation for consumer items on the industrial side. Lots of rural-based industries can be developed and khadi and village industries can help in this process. Khadi and village industries are giving a lot of assistance to various State Governments for the purpose of starting small indus-

[Shri V. Narayanasamy]

tries in the rural areas. Madam, the funds that are given are not being utilised for the purpose of developing the rural-based industies in the villages. I will cite an instance. Seventy thousand crores of rupees have been provided by the Centre to the State Governments concerned for helping the rural artisans in starting oil mills. But what are they doing? Funds are being given and the loan is sanctioned. But, the people are not utilising the funds for the purpose for which they are sanctioned. Funds are being diverted by the people who get the loan and the industry is not being started. What happens ultimately? The loan is wiped out. Why I am complaining about this is that there is no monitoring agency from the Centre. You provide funds and you close your eyes. You don't see whether it is being implemented in the right way by the State Governments concerned. This is my complaint. It is only to provide employment to the people in the villages that this scheme has been started. But what is happening? Funds are given but they are not being utilised for the purpose. Likewise, umpteen number of schemes have been introduced but they are not being fully implemented and there is no legislation in this regard. So, the hon. Minister should lay emphasis on the development of khadi and village industries. It is a means for providing rural employment apart from small scale industries. Even the agro-based industries can be started—you have a scheme for this—and you can provide funds for these industries also. Madam, I, have another complaint about the allocation of work in various Ministries. Now, you have got a separate Ministry for agro-based industries and, that is, the Food Processing Industry. What is the Food Processing Ministry doing? Lots of applications from various people for starting the agro-based industry have been received by this Ministry. But that Ministry has not cleared those applications. Already, four years have passed since this proposal was made. But the Ministry is not clearing the applications and it has not taken any policy decision. It is high time for the Ministry to go ahead with this. Only then can the Industry Ministry take the credit for having done a good job. Now, what is happening? The Government has come out with the new Economic Policy and Industrial Policy. But the bureaucrats in the Industry Ministry still think that they are in the Licence Raj. You brought liberalisation, you brought the new Economic Policy, stating that industries can be started in any area, of course, without polluting the atmosphere. But the applications, which are even under this category, are not being cleared by the State Governments and even by the Centre for the simple reason that the bureaucrats think that they are still in the Licence Raj. That tendency should go. When we are changing our policy, when we are bringing in a new Economic Policy, a new Industrial Policy, they should go with the same wind and at the same speed so as to ensure industrial development of this country. Small countries like South Korea, Hong Kong Malaysia and Singapore have developed industry. Singapore is not basically an industrial place. In these places, we find that industrial licences are given by the administration within 24 hours or 48 hours. But in India, we find that it is not the case. Environment Ministry is another bottleneck. Even if the applications are cleared by the Ministry of Industry, the Ministry of Environment blocks them saying that it is going to be a polluting industry. Therefore, there should be a proper coordination between these Ministries when licences are issued. Most of the industries which were started earlier are also polluting industries and remedial measures are not taken by those industries. Nobody objects to that. But in the case of new industries, a lot of problems are created and this is one of the bottlenecks for the development of an industrial base in this country.

I will now come to heavy industries which the hon. Minister is taking care of. Out of 48 public sector units coming under the control of the hon. Minister, more than 19 have become sick. They have been referred to the BIFR. The investment that has been made in

these public sector units is not yielding good results. They have exported goods worth Rs. 1031 crores only in 1992. The Equity Participation Scheme has been introduced and the hon. Minister is also taking steps for improving the efficiency of the public sector units. Some hon. Members have also referred to the problems being faced by the public sector units in the country. A lot of public money is being invested. Due to bad management, corruption and poor industrial relations, the public sector units including prestigious companies like BHEL, CCI which are being taken care of by the hon. Minister, are not yielding proper results. Though some of them have signed MOUs, they are not able to yield good results. We have time and again been demanding in this House that the Chairmen and the MDs of the public sector units, who manage the affairs, should be made accountable for their units. They agreed that they would do it. Ultimately, the result is a negative growth on the industrial side. The comparative figures given by Mr. Jadhav are very celar. They show that while an industry in the private sector has earned profits, the same industry in the public sector is not making profits. Various special measures have been taken by the Government such as modernisation, new technology and the recent VRs. The Voluntary Retirement Schemee that has been brought in by the Government is yielding good results. More than 90000 employees in various public sector units have opted for voluntary retirement. With the benefits under the scheme, they are doing some other business, starting some small-scale industries. However, the mismanagement which is prevailing in the public sector units is one of the major causes for the losses being incurred recurringly. I would like to submit to the honourable Minister that the scheme that has been brought, the MoU that been signed, should be completely complied with by the management. I am also on the Committee on Public Undertakings and I have seen the functioning of the public sector units. I know how the purchases are made, how the machinery is purchased, how raw materials are purchased and how the finished products are sold. The public sector units have become sick only because of bad management by the Chairmen and managing Directors of these units. Otherwise there can be efficient functioning because funds have been provided. But these units are not yielding good results because of bad management only. We also see that whenever labour problems crop up in the public sector units, they are not being managed properly. I will give you a small example. In the IPCL, the employees had to be given Rs. 48 lakhs as house rent allowance and the management was not agreeing to it and the Industry Ministry was also not agreeing. Ultimately, what happened was that the employees went on strike for nine days. They did not report for duty and the Government lost more than Rs. 28 crores. For not paying Rs. 48 lakhs to the employees, the production loss was more than Rs. 28 crores! This is nothing but bad management. It shows that timely action is not taken and better employer-employee relation is not macntained proper planning is not there. These are the major causes for the losses in the public sector units. After all, the public sector has been created for the purpose of employment generation, better production and greater productivity, but the concept is drifting away. Even in the case of the Cement Corporation of India, crores of rupees have been invested for starting industries in the backward regions for giving employment to the people and that is also in the red. The concept of public sector is slowly withering away. But the Government has taken a bold decision either to abandon or give to the private sector those units which are making losses. Why should we carry a public sector unit which, in spite of the huge amount of money invested in it, is not going to earn profits? In the textile industry, they are losing one crore of rupees a day and several textile units have been closed down. Why should the Government keep such industries with it? Why do you invest money and make losses? Therefore, the concept of public sector has to be changed and you should invite foreign invest-

[Shri V. Narayanasamy]

ment, you should invite foreign equity and you should see that the public sector units are able to yield good results and earn profits.

Then, in the industrial sector, there is a peculiar situation whsch is prevailing now. What was done earlier for the purpose of developing industries in the rural areas and backward regions of the country? A novel scheme was there. Subsidy was given to those persons who started industries. That scheme was scrapped and another scheme was brought. That is a good scheme. Various locations have been identified for developing the infrastructure. According to their estimates, this scheme will need about thirty crores of rupees for the purpose of developing the infrastructural facilities. But the provision that has been made in this year's Budget for all the Growth Centres is only Rs. 32 crores. How are you going to develop the Growth Centres in the various districts for the purpose of developing industries? I demand a specific reply from the honourable Minister because the Growth Centre concept which was started by the late Rajiv Gandhi for developing the backward regions in the country is slowly withering away. The reason is that the persons who have started industries are being told that since the growth centres are coming, they are not eligible for subsidy. And when you scrap the sugsidy scheme, it is your bounden duty to develop the growth centre in the rural areas and also backward regions so that a lot of industries will come up in the rural areas, so that people who are living in the rural areas will get better employment opportunities. Therefore, I want a specific reply from the hon. Minister about the growth centre concept that has been brought. How are you going to implement it?

Madam, this disinvestment scheme is a novel scheme About Rs. 3,038 crore worth of shares have been sold in the name of disinvestment. Madam, day in and day out, news items are appearing in the press to the effect that shares with more premium value were sold at a lesser premium by the public sector units. Though this concerns the Finance Ministry, the administrative Ministry, the Industry Ministry has also its responsibility because in the heavy industries, when they thought of implementing this disinvestment scheme, they brought out the guidelines. Under those guidelines, the schemes have to be implemented. Madam, I find that while implementing the scheme, while disinvesting the shares, we find that the shares have been undervalued and sold in the market. I would like to know who took the decision to under-value the shares when a higher rate was prevailing in the market. How have the funds been diluted? Who is responsible for taking such a decision, brining loss to the public sector units? And the Finance Ministry cannot give that reply for the reason that it is the administrative Ministry who are responsibile for its implementation Therefore, Madam, as far as disinvestment is concerned, in future they should see that the shares are sold at a competitive rate so that more funds will come to the Government. And the Government would like to get more than Rs. 3,000 crores for the purpose of utilising it for the BIFR scheme, the voluntary retirement scheme, and also for modernisation and technological upgradation of the public sector units. And whether the Government is going to get those funds is also to be seen. But in the disinvestment scheme, I find that when the decision was taken, it was taken in a haphazard manner, and the Government is not applying its mind as far as the share prices that are prevailing in the market are concerned. Therefore, it is high time the Government reviewed the scheme that has been brought for the purpose of disinvestment.

Madam, a lot of concessions are given by the Government to the multinationals to enter into various projects and industries in our country. But the hon. Members from the other side have been saying that if the multinationals will come into the country, we will loss our freedom and that the multinationals will dominate

Madam, I would like to submit that the Ministry of Industry and also the public sector units can concentrate more on the infrastructure side, and the consumer items can be left to the small-scale industries and also to the multinationals. With the anti-dumping policy of the Government, this aspect can be monitored and regulated. As far as the Government is concerned, they can concentrate on infrastructure industries, and industries in which the public sector alone can do, and where the private sector will not be able to do even by way of competition. Therefore, Madam, there can be a re-look into the public sector units. As far as the heavy industries are concerned, there is the BHEL which is a public sector unit. But I find that there is a lack of support to it. When we see the negative side, we should also see the positive side. As far as the BHEL is concerned, as far as the locomotives are concerned, we made a fervent appeal in this House that the local industries have to be given patronage and that the public sector units should be given patronage. I urge upon the hon. Minister to see that these industries are given protection. The production that has been made by these industries should be given protection by the Government. Is the Government going to purchase these items from abroad? Of course, we agree for competition in the field. I agree that there should be competitiveness, efficiency and quality improvement in the public sector units. But there should be protection given to these industries for their survival and the Government of India has to consider it and see that these industries are given protection so that income from these public sector units could be ploughed back for development of the country. Therefore, a lot has to be done in the industrial field.

There is a great potential in the country for development of agro-based industries and also for improving the efficiency of the public sector. I think the hon. Ministers who are sitting here are competent enough to take care of it. The new Industrial Policy Resolution which has been brought about is a challenge to the Ministers and they have to see that industrial development takes place and whatever assistance is needed to be given to the State Governments, it should be provided in a balanced manner. We can lend all our support to the Government for bringing about industrial development in the country. I would like to submit that the Government should see that corruption is eliminated. The industry should not be left in the hands of bad management Better industrial relations have to be maintained and there should be proper industrial development in the country in the small-scale sector and also in the sector of other infrastructures so that we are able to compete in the world market and are able to earn more foreign exchange. With these words, I conclude..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): मुझे एक मसले पर हाउस की सेंस लेनी है। अभी इस आइटम पर हमारे सामने दस लोगों के नाम बकाया हैं। अगर हमें इस चर्चा को आज चलाते रहना है और रिप्लाई आज लेना है तो हमें करीब 11 बजे तक बैठने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम चाहते हैं कि यह चर्चा कल तक चले तो फिर हम इस को अभी यहीं रोक सकते हैं और चकमा वाला मामला ले सकते हैं, मंत्री जी यहां आए हुए हैं और इस पर केवल दो-तीन लोग इस पर बोलने हैं। इस पर क्लेरिफिकेशन दिलवाकर आज हम हाउस एडजोर्न कर सकते हैं और बाकी की चर्चा कल चला सकते हैं और इस पर रिप्लाई भी कल हो सकता है। जैसा आप चाहें।

श्री सुकोमल सेन (पश्चिमी बंगाल): चकमा छोड़ दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है इसकी चर्चा आज ही होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): यह चर्चा अगर आगे चलाये रखनी है तो हमें 11 बजे तक बैठना होगा। वैसे हमारे पास डिनर का अनाउन्समेंट भी है। अगर आप लोग बैठना चाहते हैं तो डिनर का अरेजमेंट किया गया

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

है साढ़े दस बज तक । आप जैसा चाहे । अगर आप चाहते हैं यह चर्चा चलती रहे तो चकमा वाला कल ले लेगे । पर यह चर्चा चलाते हुए आपको साढ़े दस, ग्यारह बजे तक बैठना होगा ।

श्री सुकोमल सेन : इसको आज ही ले लें

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप ग्यारह बजे तक बैठना चाहेंगे ? इसी चर्चा को चलाकर खत्म करेंगे? ठीक है जैसी आप लोगों की राय हैं, इस चर्चा को आगे चलाते हैं और चकमा वाला कल लेते हैं ।

श्री छोटूभाई पटेल (गुजरात) : जो बाहर ड्राइवर बैठे हैं उनके लिये खाने का क्या इन्तजाम किया हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप किनकी बात कर रहे हैं ?

श्री छोटू भाई पटेल : जो बाहर ड्राइवर बैठे इन्तजार कर रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगर आपके निजी वाहन का ड्राइवर है तो अलग बात है ।

श्री छोटू भाई पटेल : मैं एम. पी. स्पशल के ड्राइवर की बात कर रहा हूं जो बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। उनको खाने के लिए नहीं बुलाया जाता ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ऐसा है कि एम.पी. स्पेशल के ड्राइवरों को खाने का समय मिलता है । दोनों समय उनको खाने का समय मिलता है । उनका हाउस के देर से चलने का कोई लाल्लुक नहीं है ।

श्री छोटू भाई पटेल : सब का इन्तजाम होना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): I have one announcement to make regarding dinner. As the House is sitting late.....

SHRI V. NARAYANASAMY: Tomorrow also we have to sit till late because there is a lot of business to be finished. Therefore, we should finish our discussion today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): So, the sense of the House is that we will continue with the discussion.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): How many speakers are still left?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): About ten.

SHRI ASHIS SEN: Can't we reduce the time for the speakers?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Time is already allotted to the parties. We cannot do anything about it. So, the sense of the House is to continue this discussion. The House will sit late. Now, dinner has been arranged for the members and also for the officers and staff and members of the Press between 8.30 and 10.30. All are cordially invited.

Now, Shri Sunil Basu Ray.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Madam Vice-Chairman, we have been discussing so long and, perhaps, we will be discussing for some more hours this most important issue which is haunting us, namely, the question of industrial development, the question of removal of industrial sickness and other related problems. We are facing a very serious situation.

Madam, the other day, in this House, while replying to the debate on the Finance Bill, the Finance Minister, in response to a query, said that the allegedly sick industries must wither away. This declaration was, however, supported by facts.

In 1989, there were 108,748 sick units with a bank credit of Rs. 207.57 crores. In 1990, there were 141,162 sick units

with a bank credit of Rs. 287.26 crores, which were 'not traceable/not in existence', according to the Reserve Bank of India Bulletin, 1991-92. Table II. 16. The Reserve Bank of India itself had admitted that such a large number of industrial units could not be traced or, perhaps, they were not in existence at the time of reporting. But the figures for the last two years themselves show that the units are very much in existence. Perhaps, this withering away was due to their neglect by the industry Ministry.

In 1990, there were 2,25,324 SSI sick units with a bank capital of Rs. 2,611 crores. There were 1,467 non-SSI sick units with a bank capital of Rs. 4,734 crores. There were 'weak units' also. As on 31.3.91 there were 1,342 non-SSI sick units in the private sector, 111 in the joint sector and 8 in the co-operative sector. The total bank capital is Rs. 5,105.60 crores. Similarly, there were 554 non-SSI weak units in the private sector, 279 in the public sector and 13 in the joint/co-operative sector with a total bank capital of Rs. 2,869.31 crores. This makes a grand total of 2307 units with a bank capital of Rs. 7,974.97 crores.

Madam, the failure of the Industry Ministry to implement the 1956 Industrial Policy Resolution is palpable from these figures.

The highlight of the achievement on the industrial front is the growing cancerous sickness in public sector. The two-volume monograph and the subsequent report of the Labour Consultative Committee on these industries and several other reports have proved that there were serious wrongs committed on the industrial front.

The industry Ministry, which is the nodal Ministry for heavy, small-scale industries, for policy determination, for monitoring industrial relations in the public sector and for watching the wholesale price index, has failed. This is because the Government was not sincere in strengthening the industries. The P.S Us sufferel the most, causing similar agony in the private sector as well as in the SSI sector. Thus, the nation suffered. The workers suffered.

In 1990-91, there was a great change for worse. An era of deindustrialisation set in. An era, in fact, of inudstry-cide. The entire economy, all of a sudden, faced the stark reality of disintegration. How did it happen? The World Bank/I.M.F. had given us some loan under certain conditionalities in 1980-81. On 30th November, 1990, they sent a report to the Government of India—No. 8995. It was accepted by the Rao Government on 21st June, 1991. Among various conditionalites there were directives for budget reforms devaluation, amendment of Trade Rules, restricted and concise list of import, de-licensing of capital goods and intermediates, relinquishing of Government monopoly over import, reduction of customs to preferably zero level or a common customs duty of 20 per cent, OGL for consumer goods, Reform Export Policy for the import of export-oriented machinery goods, rebate on import duty be given for a period of three to 5 years and several trade related directives followed by change in Industrial Policy. The directive was to remove the restrictions, remove protections given to the industries, priority for domestic industries to be given up; reorganise PSU, units running at a loss to be closed down; surplus staff in ndutsries to be retrenched, creating a fund for compensation, disinvestment of PSU shares.

Fulfilment of all these are embodied in the NIP Resolution and all subsequent economic and industrial documents of the Government.

As a result, BIFR Act was amended. Now, there is a proposal to further amend it so that all PSUs can be automatically referred to BIFR. which means its liquidation.

Companies Act, Industrial and Mining Act, Export Import Policies, industrial Relations and Trade Union Bill, are either being amended or are in the process of being amended to suit the new policies. New bills are in the offing.

[Shri Sunil Basu Ray]

During post-Policy period August 1991 to December 1992, foreign investment approval amounted to 7 times of the August 1990 to December 1991, equivalent to Rs. 42.9 billion. In 1992 1520 foreign collaborations were approved U.S.A. had a share of 31.7 per cent, Switzerland 17.7 per cent, Japan 15.7 per cent. Sixty-seven foreign companies raised their equity to 51 per cent or more. The major areas of foreign collaboration are: Oil refinery, chemicals other than fertilizers, electrical equipment, food processing, hotel and tourism, transportation, textiles, telecommunication power, metallurgical industries.

More paterns are being received from foreign companies. During April-October 1992 to November 1992-March 1993, as against 318 patents from Indians, 1112 were recevied from foreign companies. Government's intention to borrow money internationally at the rate of 16 per cent for power sector will give a free hand to the creditors and spell doom for our industry and economy.

(The vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy) in the Chair)

Sir, this is the situation with which we are confronted. We are witnessing the result of the implementation of the Industrial Policy Resolution, how it is affecting our national economy. In the new Industrial Policy declared in July 1991 licensing proceedure was changed. Obtaining licences for 18 months was made necessary. Foreign companies can now invest or make cent per cent investment in Indian industry. 173 industries which were given protection in the public sector, their number has been reduced to zero. Under the new national mining policy declared on March 5, 1993, several industries reserved for the public sector, will be given to the private sector. This is so in the coal mining industry. The Coal Mining (Amendment) Act has been passed for this purpose. On January 15, 1992 the steel prices were decontrolled, and the priority given to the domestic industries in purchase was also withdrawn. In 1992-93 the distrbiution and prices of phospetic fertilizers, kerosene and cooking gas were decontrolled. Restructuring of the public sector was announced in the new industrial policy, and it was decided to refer the case of sick industries to the Board of Industrial and Financial Reconstruction. In 1991-92 it was decided to retire additional workers under the golden handshake plan and the voluntary retirement scheme. In 1991-92, for the employees affected by the exit policy a new trainign and rehabilitation porgarmme was announced, and a decision to set up a reconstitution fund of Rs. 200 crores for this was also taken. But none of these schemes has yet been implemented. In 1992-93 a sum of Rs. 1,000 crores was allocated for this fund. In 199192 shares worth Rs. 3.38 crores of 31 undertakings were sold. In 1992-93 shares worth Rs. 3,500 crores were earmarked to be sold. Out of these, shares worth Rs. 1,866 crores of 13 undertakings were sold, and tenders were invited for sale of 5 per cent shares of 15 undertakings. Now, thus, what is happening is that our conventional idustries in the public sector are being dismantled. Our industries in the private sector, in the co-operative sector and in the joint secor are becoming sick, and no new industry is coming up. That is the net result of the poliy that is being pursued by the Government through the Ministry of Industry.

What should we do? If we allow the present policy to continue, then, our industries will be in the grip of foreign monopoly capital. It is already evident from the figuers reecived that multinationals have increased their stokes in Indian ompanies as a consequence of liberalisation. There are about 27 companies the names of which have come in the Press, in which at present they have more than 50 per cent shares. In this way, our industries are becoming subservient to the interests of foreign monoply capital.

Not only this, but the way the export and import trade is being regulated, the customs and excise duties have been given a farewell and they are no more in existence. As a result, foreign goods will have ample scope of being dumped in our ountry. As a result of recession in Europe, in the USA and in other developed, industrialised countries, they are now in a position to send their goods to our country without any hindrance and our industries are already facing obstacles as a result of this.

Take, for example, steel. We are still undecided about its future. We do not know whether it will be in the public sector, whether it will be in the private sector or it will be anywhere else. But the demand for steel that is there in the counrty, is being me partially through imported steel. The more the percentage of imported steel, the dimmer the prospect of rejuvenation or revamping. It will not be possible to revamp it. The trend that is visible leads us to believe that it will be sent perhaps to BIFR, as has been said by the Minister that unless the workers concede, they will send it to BIFR. That is 9.00 P.M. they will send it to liquidation. On the one hand the foreign goods are beig dumped into our country as a result of which our industries are facing a serious crisis. On the other hand the policy of revamping the old industries is not being effected following a rational policy. That is the reason why our indigenous industries are suffering. Unless we do something, there will be deterioration in our industrial climate. Moreover it will cause unemployment. Already three crores workers have been rendered unemployd in the urban areas. This number is on the inrease. Who is going to give them relief? Where will they get employment? Whtre will the self-employed workers get market? There will no market facility, because the entire market will be in the grip of the big traders and foreign monopolists. They will squeeze the indigenous industry.

Now, I come to the question of voluntary retirement benefits. It mens there is no question of industrial trading or rehabilitation of the workers. This money is being paid as a bribe so that they may not dare to protest against this policy. The result is that thousands of workers are going out. The industry is also going out. In the NTC already 27 thousand workers have gone out. There are several thousands more in the waiting list. The NTC, as an industrial unit, is going out. So, unless we top this process of disintegration on the industrial front we will be unable to protect our industrial independence and industrial self-reliance. In this context, if you permit me, I will refer to the first. Report of the Department Related Parliamtenary Standing Committee on Commerce as also the Report on Industry. Both the Reports have drawn the Government's attention to immediate problems. The Commerce Committee Repot says: "Moves of the developed market economies to dump their products such as DAP fertilisers and PVC resins in India are causing concern for our industry. Then comes the question of indigenous industries which are being affeted as a reuslt of the recent liberalised import policy. Thus the imported finished goods are made cheaper. As a result this is likely to result in closure of caustic soda units. Cohin Refineries is stated to have stopped manufacture of Benzene as a result of reduction in the customs duties etc. The Committee is of the view that no protect the indigenous industry, the import of capital goods should be selective and, when required, essential component only should be permited. Unrestricted imports are bound to adversely affect our Balance of Payments and self-reliance, which is one of the objectives of the Export-Import Policy."

In conclusion the Committee says: "Given the potentiality of the Indian market, there objectives could be objectives with rigoous growth or else we will lose our self-reliance.' I want to draw your attention to another factor that the cost weakness in our public sector industries is also due to wrong

[Shri Sunil Basu Ray]

policies being pursued. For example MAMC is a factory at Durgaur, which was designed to produce mining machinery. Now, it is also an imported machinery. They just repair it and make it workable for the mining industry. But proper quality of steel is not available to manufature those components. The steel that we get from our industries is not suitable for manufacturing those components. It is a serious factor.

Another factor to which I must draw the attention of the Government is to the cycle industry. The cycle industry has been referred to the BIFR. For example, the Bscycle Corporation of India has been referred to the BIFR. The Cyle Corporation of India is also on the same path. But the Department of Industry in its Annual Report says that big cycle units can produce only frames, rims and chains and other component will have to be produced in the small scale sector. I do not know whether those small scale units are in a position to manufacture them or not. If they handle these things, then, there will not be any cycle. If this sort of non-planned, non-thought out policies are imposed on the industries. then, these industries cannot survive. So there must be a review of the industrial policy. The sooner a reversal of the industrial policy and a reversal of the economic policy that are being pursued by the Government is done, the better it would be; otherwise, the country will face a serious situation for which the Government will have to bear the responsibiliy. (Ends).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chhotubhai Patel, your time is fifteen minutes.

श्री छोटू भाई पटेल : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हाऊस में चेयर की ओर से समय की पाबन्दी के बारे में भावनायें रखी गई हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं हाऊस का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सर, सरकार ने जो 24 जुलाई, 1991 को इंडस्ट्रियल पालिसी का जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें लगता है कि काफी सुधार करने की इंडस्ट्रियल पालिसी में कोशिश की गई है, मगर इसके बाद भी सरकार, ने खास करके वित्त मंत्री जी ने काफी लिब्रलाइजेशन पालिसी में किया है और काफी छूट-छाट भी दी गई है।

इस हाऊस में जो कोई हमारा इंडस्ट्रियल पालिसी का रेजोल्यूशन जो 1948, 1956 में रखा गया था, और उसके बाद का जो स्टेटमेंट 1973 का है, 1977 का है और 1980 का है, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मगर यह हमारे भूतकाल को मद्देनजर रख कर हमारी सरकार ने जो परिश्रम उठाया है, इसमें सरकार की जो नीयत है, वह प्रशंसनीय नीति लगती है और उसकी जो भावनायें हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं।

मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट के बारे में जो देश में बात कही गई है, इसका इंप्लिमेंटेशन सरकार अच्छी तरह से करवायेगी, तो मुझे लगता है कि आम जनता को कुछ फायदा इससे मिल सकेगा।

हमारी जो प्रमुख उपलब्धियां 1992 तक की जो हैं, खास करके हैवी इंडस्ट्री की, इसमें भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत निर्यात में जो वृद्धि हुई है, वह 45 प्रतिशत हुई है। वह सराहनीय बात है। इतना ही नहीं, मगर 49 उद्योगों के विभागों में जो उत्पादन हुआ है, इसमें भी 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमारे देश में जो भारी उद्योग हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें जो एच0एम0 टी0 है, भेल है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हैं, ऐसी कई भारी, हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, ... उसमें निर्यात के बारे में और उनके प्रोडक्शन के बारे में अहम रोल इस देश में दिखाया है। यह हमारे लिये अच्छी बात है। हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट का प्रोविजन भी करीबन

15.06 प्रतिशत इस डिपार्टमेंट के लिये किया है, वह भी अच्छी बात है । वह इकोनोमी को रिड्यूसल करने के लिये, इंडस्ट्रियल पालिसी को डायनामिक बनाने के लिये और जो ब्लास्ट एरिया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का और रिमोट एरिया का उसको डिवैलप करने के लिये भी इसमें प्रावधान किया गया है । हमारी नीति अच्छी है इसमें कोई शक की बात नहीं, मगर सर, जो दहशत, शक इस देश में हरेक को रहती है वह वही है कि हम जो सुधार करते हैं उसका फायदा आम जनता को मिलता है या नहीं, वह अहम बात है । चाहे स्पोर्टस की बात हो, चाहे चुनाव की चाहे कंपीटीशन की बात हो, चाहे देशी और विदेशी कम्पनियों के कंपीटीशन की बातें हो, इसमें विजय पाना, जीत पाना, यह अहम बात है । जब सपोर्ट्स में जीत नहीं मिलती है, चुनाव में हमें जीत नहीं मिलती है और इंडस्ट्रियल पालिसी के तहत आम जनता को नहीं जीता जाता है तो इंडस्ट्रियल पालिसी में भारी कमीनापन लगेगा, ऐसा मुझे अब लग रहा है । इसलिये कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है इसकी जो फिलासफी है, इसका कंसैप्ट है, इसका जो परकोलेशन होना चाहिये आम जनता तक पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच पाता है । फाइनांस मिनिस्टर ने जो हमें छूट दी गई है, वह एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी, में जो रिड्यूसल किया गया है, उसका लाभ जो आम जनता को नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि जो फैसेलिटी दी गई है, जो कंसेशन दिया गया है उसका लाभ हमारे एंटरप्रिन्योर्ज जो हैं उसको उठाना चाहिये । वह नहीं उठायेगा तो मुझे लगता है कि इसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पायेगा । इंडस्ट्रियलिस्ट जो कुछ प्रोडक्शन करता है उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिये । फाइनेंस मिनिस्टर ने 4500 करोड़ की जो छूट दी गई है, सर, उसका बैनिफिट अब तक आम जनता को नहीं मिला है । हाउस में जो बात को कही है, आम जनता की बात, मास की बात और क्लास की बात कही गई है, 20 परसेंट जो क्लास है उसको बैनिफिट मिल रहा है, मगर मास को बैनिफिट नहीं मिल रहा है । यह हमारा गरीब देश है । इसका कंसैप्ट है कि आम जनता को, मास को उसका बैनिफिट मिलना चाहिए मगर हमारी जो अभी इंडस्ट्रियल पालिसी के तहत मुझे यह लग रहा है मैं देख रहा हूं कि मास को लाभ, बैनिफिट जो मिलना चाहिए, वह बेनिफिट हम नहीं दे पा रहे हैं, इसका मैं एहसास कर रहा हूं । मगर क्लास को बैनिफिट मिल रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं । यह इंडस्ट्रियल सैक्टर में एरिया में जो इंडस्ट्रीज को अहम रोल दिखाना है, वह अहम रोल नहीं दिखायेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे तब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेनेफिट हमें नहीं मिलेगा, कनवर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का बेनेफिट हमें नहीं मिलेगा । सर, जो धुर्त लोग होते हैं, वह भूखों नहीं मरते । हमारे देश का जो लाभ है उसका फायदा उठाने के लिए जो विदेशी धुर्त लोग हैं, वह ओपन मार्केट के तहत कोशिश कर रहे हैं । मगर मैं इस कंसेप्ट को मानता हूं कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास कलम की शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, धन की शक्ति है, उसका संचय कर उसका बेनेफिट जो छोटे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको उँगली पकड़कर खींचना है, उनको उठाना है । उनको ताकत देना है । इसी तरह जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें छोटी इंडस्ट्रीज को सहाय करना है, असिस्ट करना है । उसके लिए हम ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोशिश की है, मगर उसको सहायता नहीं मिल रही है । सर, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, यह वास्तविकता है । तो इस देश में जो 80 परसेंट छोटी मछलियां हैं, उनको 20 परसेंट बड़ी मछलियां खा न जाएं, इस बारे में हमें गंभीरतापूर्वक ध्यान देना

[श्री छोटू भाई पटेल]

है। **वह मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना** चाहता हूं। हमारे देश में खासकर राजीव गांधी के समय में हमने जो ग्रोथ सेंटर बनाए थे, उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। उसमें कभी नहीं रहनी चाहिए। हमारे यहां कितने ग्रोथ सेंटर इम्प्लीमेंट हुए हैं, कितने मिनी ग्रोथ सेंटर इम्प्लीमेंट हुए हैं। हमारे यहां जहां कि 10–12 कलस्टर ऑफ विलेजेज हैं, वहां हमें मिनी ग्रोथ बनाना चाहिए ताकि हरेक सेंटर को शासन की ताकत मिल पाए।

सर, हरेक देश तब तरक्की कर सकता है जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशियो एकोनोमिक स्टेबिलिटी रहे। सामान्यतः पालिटिकल स्टेरेंबिलिटी हमारे देश में रही है, मगर सोशियो इकोनोमिक स्टरेंबिलिटि हमारे यहां नहीं है। उसे लाने के लिए इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री को काफी अहम रोल अदा करना है। अगर वह नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि जनता को जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। आदरणीय अरुणाचलम जी यहां बैठे हैं। वह पहले भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, मैंने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से साउथ गुजरात में बलसार डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे करवाने के लिए मंत्रीजी को लेटर दिया था और उसके मुताबिक सर्वे हुआ था। इस सर्वे के मुताबिक हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी ने जो बात कही थी, अब तक उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसमें कहा गया था कि जिस तरह कच्छ डिस्ट्रिक्ट में नौसरी ताल्लूक के कोस्टल एरियाज के विलेजेज में चाहे बोकारो हो, चाहे भिलाई हो, वहां जन्म से जो टैक्नीकल स्किल डवलप हुई है, उसको डलवप करने के लिए, उनको टैक्नीकल टर्नस की बात, फिटर की बात, वरेल्डर की बात सिखाने के लिए जो आय.टी.आय. की सुविधा होनी चाहिए लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे इंडिस्ट्रियल मिनिस्टर ने पहले वह बात कही थी, लेकिन अब तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहां आवश्यकता है, आवश्यकता के मुताबिक हमें वहां काम करना चाहिए। अभी अभी हमारे बिहार की आदरणीय बहन जी, साथी ने जो बात कही इमबलेन्सेस है, इसी इमबलेन्सेस के बारे में मैं कह रहा हुं, आदरणीय मंत्री जी, कि जहां ठोस कदम उठाना चाहिएं, टैक्नीकल नोहाऊ जहां जन्म से डवलप होती है, उसका स्किल्ड डवलपमेंट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो टैक्नीकल इंस्टीट्यूट यहां बनना जरूरी है, वह हम नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां बिना सिखाए जो लोग हैं, वह वर्ल्डिग कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की वर्ल्डिग क्यों न हो, वह कर सकते हैं, बिना सिखाए कर सकते है। हमारे यहां जो स्किल डवलप हुई है, उसको मजबूत बनाने के लिए डो कदम उठाने की बात रिपोर्ट में कही गई है, अब तक उसका कुछ इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि मिनी ग्रोथ सेंटर की बात स्वीकार की गई है, उसका इम्पलीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी कुछ सीरियसली सोचा जाए। ... **(समय की घंटी)** ...

THE VICE-CHARIMAN (SHRI V. NARAYANASWAMY): Kindly conclude.

श्री छोटू भाई पटेल : मैं कलक्लु कर रहा हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। But, Sir, I wish I will get justice from the Chair.

उसके बाद हमारे देश में यह जो इंडस्ट्रियल पालिसी रखी है, वह इंटिग्रेटड कम्प्रेहेंसिव इंडस्टियल पालिसी होनी चाहिए। अभी जो पालिसी देश के सामने रखी गई है, इसमें बहुत कमियां हैं। इन कमियों को दूर करके यह इंटिग्रेटेड कम्प्रेंन्सिव पालिसी देश के सामने रखनी चाहिए। अभी एग्रीकल्चर, फाइनेन्स, टैक्सटाइल, इसके साथ जो तालमेल होना

चाहिए, वह तालमेल नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से जो तालमेल होना चाहिए, वह तालमेल नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारी हैवी इण्डस्ट्रीज जो है, लघु उद्योग जो है, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, हमारा के.पा.आई. जो है, ग्रामोद्योग जो है, हमारी टाइनीज इंडस्ट्रीज जो है, उसके साथ कोई तालमेल नहीं है। इससे होता क्या है कि जो ताकत वाला आदमी है वह ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा है और जो कमजोर आदमी है वह कमजोर होने जा रहा है। इन दोनों के बीच जो गेप है, वह गेप बढ़ता जा रहा है।..
We have Bridge the gap between have and Havenoos

ताकतवर और कम ताकतवाले के बीच में जो गेप है वह पूरा करने के लिए आपको मदद करनी चाहिए। ... (*समय की घंटी*)

सर, एक लास्ट बात, समय का अभाव है, मैं यह कहना चाहूंगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा जितना देना चाहिए, वह नहीं दे रहे हैं। हमने एटथ फाइव ईयर प्लान में 10,000 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। आप मुझे बताइए कि इतनी रोजगारी हम कौन से सेक्टर में दे पाएंगे। एक तरफ तो दिन ब दिन हम कर्मचारियों को कम करने जा रहे हैं और किसी भी सेक्टर में कोई एम्पलायमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे आप दे पाएंगे? मैंने बार-बार हाउस में भी कहा है, और जगह भी कहा है। पी.एस.यू. में हम पैसे दे रहे हैं, वहाँ काम कैसा है, यह आप जानते हैं। हमें मैनेजमेंट को सुदृढ़ करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। जो एकाउण्टेबिलिटि फिक्स करनी चाहिए, वह हम नहीं कर रहे हैं। जिसकी रेस्पोन्सिबिलिटि है उस पर जो एक्शन लेना चाहिए, वह एक्शन हम नहीं ले रहे हैं। हमें यदि इसे मजबूत करना है तो जिस पर एक्शन लेना है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। पी.एस.यू. जो मजबूत होना चाहिए, उसे जो सफलता मिलनी चाहिए, वह सफलता नहीं मिलती है। हमारे देश में सफलता आखिर क्यों नहीं मिलती है। एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज का मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारे देश में जो फूड्स एण्ड वेजिटेबल्स हैं, 0.04 हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ...क्योंकि हमारी पोटेंश्यलिटी काफी ज्यादा है। हम एम्प्ला की बात करें, तो सिर्फ 1,442 करोड़ रुपए का ही हम एक्सपोर्ट कर पाए हैं। इतनी पोटेंश्यलिटी है, 7,500 कि.मी. का हमारा समुद्र का किनारा है, इतनी पोटेंश्यलिटी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जितने करोड़ रुपए चाहती है, उतना रुपया हमें नहीं फिशरीज से ही मिल सकता है, मगर उसको जितना बढ़ावा हमें देना चाहिए, हम नहीं दे रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please conclude.

श्री छोटू भाई पटेल: मैं खत्म कर रहा हूं। लास्ट प्वाइन्ट मैं यह कहना चाहूंगा कि वह जो मैंने संतुलन की बात कही हैं इंटीग्रेटिड कंप्रिहेंसिव पालिसी की जो मैंने बात कही है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो ताल-मेल होना चाहिए, ताना-बाना जो ठीक होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। तो स्टेट्स के साथ बैठकर, उसको प्रोत्साहित करके, ऊर्जा के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जितनी हमारी इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देकर, प्रोत्साहन देकर हमें इसके साथ मिलकर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। हरेक स्टेट में जनरली सी०एम० के पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की कमेटी होती है, इस बारे में सात-आठ सब कमेटियां होती हैं, मगर एक कमेटी की मीटिंग भी नहीं होती है। मैं इस बारे में काफी एग्जेम्पल दे सकता हूं, मगर मैं कहना नहीं चाहूंगा। तो उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वह हम नहीं कर सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I am calling the next speaker. Please conclude.

श्री छोटू भाई पटेल: अंतिम बात कहकर में कनक्लूड कर रहा हूं कि हमारे देश में लघु उद्योग जो हैं, उनमें से दो

[श्री छोटू भाई पटेल]

लाख लघु उद्योग बीमार पड़े हुए हैं। हमारे उद्योग कैसे बीमार होते हैं, यह बीमारी हम जानते हैं, इलाज भी हम जानते हैं, मगर इसका कारगर उपाय हम नहीं करते हैं जानने के बाद भी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि सेंटर और स्टेट के साथ हमारी जो फिलास्फी है, हमारा जो कांसेप्ट है, उसके परकोलेट होने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यह कदम अगर हम उठाएंगे तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी इंडस्ट्री में जो कोशिश कर रहे हैं, दिल और दिमाग से, वे उसमें कामयाब रहेंगे।

SHRI MISA R. GANESAN (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak on the working of the Ministry of Industry. Sir, we have to accept certain basic facts in the industrial sector Self-realiance has been achiveed in basic capital goods. Indigenous capabilities have been established to the point of virtual self-sufficiency so that further expansion in various sector such as mining, irrigation, power, chemicals, tranport and communication can be based primarily on indigenous equipment.

Today the country ss in a position to provide consultancy services as well as managers technicians and skilled workers for setting up industrial projects abroad.

A significant aspect of industrial development during the last several years has been the predominant role assigned to public sector in establishment of basic industries.

The public sector has taken initiative for development of various industries such as steel, non-ferrous metal, petroleum, coal, fertilizers and heavy engineering.

It has also made investment in consumer industries like textiles, drugs and pharmaceuticals, cement and sugar.

The number of public sector enterprises which was only 5 in the year 1951, rose to 244 in 1990. But now the new Economic Policy is going to hit the Indian industry severely. Many industries have already come under attack. Given the way the Indian Government is surrendering to the demands of the World Bank and the IMF, the country is all set to turn into a colony of the West.

The new Economic Policy and the Indusrial Policy being pursued by this Government are bound to enslave India in not too long a time. These economic reforms could be more detrimental than one can imagine. They are going to ruin our industry, socio-economic infrastructure and of course, lead to economic dependence on the western institutions. Saying that we are gong to pave the way for industrial development, a new Industrial Policy was announced in July, 1991. This is to usher in an era of liberalisation, deregulation and technological advancement opening up the economy to foreign investors. The Government wants the foreign companies to invest in India for an all round development of the country. To achieve this, the Government has slashed custom duty. Customs duty to the tune of Rs. 7000 crores has been done away with. The MRTP and FERA regulations have been amended. This has made possible the taking over of the Indian companies by the multinational companies. As of date, more than 2000 foreign companies are operating in India and their total investment is about Rs. 2300 crores. Most of this investment is in the form of technology expenses. Over the years, these companies have remitted Rs. 2500 crores to their respective countries as technoogy fee. This doesn't include profits and other benefits. The sad part of this is that the technologies which these companies are bringing are absolute and had been discarded long back in their own countries. This has mainly been used for producing less important items like fast food, cold drinks, lipsticks etc. which either the Indian companies were already making or were capable of making. Then, owing to the reduction in customs duty, the domestic industry

is on the verge of collapse. The Paradeep Phosphates Limited, the Deepak fertilisers and the units of IFFCO manufacturing DAP have already closed down. The Paradeep Phosphates Limited, one of the biggest factories in Asia manufacturing di-ammonium phosphates (DAP), was closed down on 31st March, this year. What was the reason? It was said that this company could not market its product worth Rs. 180 crores stored in the godowns due to the glut in the market. The Government waived the customs duty on DAP and, because of this the imported DAP was made cheaper by Rs. 1120 per tonne. The fertiliser produced by the Paradeep Phosphtates Limited costs Rs. 6080 per tonne whereas the imported fertiliser now costs justs Rs. 4690 per tonne. It is an admitted fact. And now the Department of Fertiliers has asked the public sector fertiliser companies to import di-ammonium phosphate to build stocks for adequate and timely supplies to the farmers during the coming kharif season. This has come out in yesterday's newspapers also. The Department says that the companies should take advantage of the prevailing low prices of the complex fertilisers in other countries for the benefit of the growers. This is the result of the new Industrial Policy. Sir, due to the coditions imposed by the World Bank, not only the companies involved in the production of fertiliser but the companies producing benzene, plastics, machines, PVC resin, glass, etc. are also facing a shortfall in demand. These industries are under severe threat from the multinationa companies due to their free access to the Indian market.

Di-ammonium sulphate was decanalised and decontrolled and import duty on it was completely waived. The benzene industry is also facing problems. The Cochin refineries due to financial hardship, has abandoned its expansion plan. The import duty on benzene has been reduced from 40 per cent to 15 per cent. Besides, no sales tax is levied on it. But on locally produced benzene, duty is levied at the rate of Rs. 5185 per kilolitre. This has made the import of benzene lucrative. Same is the case with other industries too. As a result, nowadays, the people are more interested in buying things from abroad than from the Indian market. When our hon. Prime Minister inaugurated the 65th Annual Session of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry on October 10 in Delhi, he said, "The original reasons for introducing Controls were convincing and they served the nation well, Later, it began to delay decssion making reduce competition, shelter, inefficiency and discouraged initiative. Since the Controls did not assist the economy to become globally competitive. major changes were introduced and they would now be carried to their logical end." This was the speech of our hon. Prime Minister. What is its logical end? Its logical end now will render one crore people jobless. As many as 3.5 crore people registered in the employment as on March, 1993, would have not of getting a job in the near future.

The World Bank, in its November, 1990 report on "Policy for the improvement of trade in India", had suggested that labour force should be reduced in various industries and the sick units should either be closed or reorganised. Abiding by the directive, the Government has reorganised several units and is also formulating an exit policy. The exit policy should not throw people into distress. The case of 58 public sector companies is being handed over to the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). Along with this, to reduce the number of labour force in the industries employees are forced to take voluntary retirement. Rs. 148.75 crores were disbursed by the Government to public sector enterprises to enable workers to avail of this voluntary retirement scheme. In an over-populated country like India where millions of hands are without work, labour-intensive techniques in the industry are most suitable. But our Government, keen to oblige the World Bank, is allowing the import of automatic and robot-based machinery for production. These production techniques are causing heavy unemployment in countries like UK,

[Shri Misa R. Ganesan]

USA, Germany and Japan which have much less population than India. Instead of creating more job opportunities, the Government is out to snatch away the jibe. In the public sector textiles industry, for instance, 23,358 workers were retrenched by January, 1993. In the next one year, another 45,000 workers would be retrenched. Out of 22,19,000 workers employed in the Central public sector units, 4,72,000 would lose their jobs.

The conditions laid down by the World Bank and the International Monetary Fund have compelled the Indran Government to relax its Foreign Exchange Regulation Act (FERA) and company laws. This has resulted in the multinational companies' taking over the Indian companies. To further facilitate the take-overs and mergers, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (MRTP), an obstacle in merger of one company with another, has been amended. Earlier, permission had to be sought from the MRTP Commission for such moves. Multinational companies are misusing their power to hold 51 per cent equity shares in the Indian companies and are out to sideline their Indian managements. These companies will take decisions in keeping with the interests of their respective countries, without caring for their repercussions on the Indian economy. In Maruti Udyog Limited, Suzuki's share has gone up from 40 per cent to 50.24 per cent. So, now it is no more a public sector enterprise, but a Japanese company for all practical purposes. The multinational company, Hindustan Lever, has finally taken over the Tata Oil Mills Company Limited (TOMCO) run by India's biggest business house, Tatas. The company, making popular soap brands like Hamam and O.K., is no more in the hands of the Indian management.

As a result of the take-over Hindustan Lever possesses one-third share of the total soap and detergent market which is neither good for the country nor for the consumers. It is sure to exploit its buyers due to its monopoly in the market with commercial interest dominating its market strategy rather than consumers' satisfaction. The Government's claim that the entry of multinational companies would encourage competition in the market and it would be good for the growth of the Indian companies is proving to be false as the Indian companies are being sucked up by the giant multinational companies.

After Hindustan Lever's take-over of TOMCO, its parent company, UNILEVER, has increased its share capital to Rs. 150 crores in India, thus further expanding its economic empire. Now, it is trying to grab Brooke Bond and Chessoberro too. Similar is the case with small-scale companies. Having been allowed to hold 24 per cent shares in the small-scale companies, the MNCs are fast capturing them. The waiving of licence for this sector has acted as an incentive.

Before I conclude, I want to emphasise that though this policy seems to be bold, innovative and growth-orinted, absence of a proper system to take care of liberalisation, steep hike in the interest rates of financial institutions and lack of infrastuctural facilities will create hindrances in implementing the same. Sir, yesterday, I saw an alarming news item in the "Indian Express" with the caption, "Disappointing show by core industries". They have clearly stated that the performance of the basic and infrastructure industries, crucial for the success of the economic reforms process, has been disappointing in 1992-93 as compared to the previous year. I am not reading out the full news item for want of time. But the caption is, 'Disappointing show by core industries.", which is the result of the new industrial policy. So, from this news item one can clearly understand in which direction our Indian industries are moving because the new industrial policy has done all these things.

Therefore, Sir, my humble submission to the Minister is that this requires a serious consideration by the Ministers themselves. Otherwise, you may not get the desired results of your policy. The

direction in which you are moving is very dangerous.

With these words of warning, Sir, I conclude. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. Narayanasamy): Now, Mr. Muthu Mani. Your time is only six minutes. Don't complain later that I have not given you more time.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu) : Sir, I was expecting to be called by you. Since I want to finish my speech within five or six minutes, I will co-operate with you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you for your co-operation.

SHRI S. MUTHU MANI: Thank you very much, Sir, for providing me this opportunity to deliver a speech on the working of the Ministry of Industry.

As I rise to speak on the working of the Ministry of Industry, I cannot but think of the serious damage caused to the native industries because of the new economic policy. Economists and even laymen of this country look at the policies of this Government in this way. The Government has become a butt of ridicule for abandoning the time-tested industrial policy. You have opened the floodgates for the multinationals with an ulterior motive. I charge that the industrial policy of this Government is anti-worker and imperialistic. The Prime Minister, the Finance Minister and the Industry Minister had repeatedly assured inside and outside this House that there would not be any retrenchment of workers But, contrary to that assurance, lakhs of workers have lost their employment and livelihood. I can understand that the decision of the Finance Ministry weighed heavily on this. But the Ministry of Industry should have sounded the Finance Ministry about the damages such a policy would do to the native industries and workers. It is unfortunate that the Congress(I) Government is pursuing a different industrial policy for the non-Congress(I)-ruled States. The honourable Chief Minister of Tamil Nadu has taken certain steps to bring about industrialisation in a big way. Many schemes for setting up of various industries have been sent to the Centre which has put all these schemes in the cold storage. I wish to cite a few examples by way of illustration.

The Hindustan Photo Film had a proposal for manufacturing cine colour positive films at Ooty and a letter of intent was obtained in 1981 itself. The cost of the project was estimated at around Rs. 250 crores. But the Centre was keeping mum for ten years and the cost has, therefore, escalated now by leaps and bounds. Many projects like the Trade Fair Complex, the satellite port project at Ennore and the Sethusamudram project have not been given the importance and priority that they deserve. A lot of impediments are there coming in the way of industrialisation in Tamil Nadu despite the fact that Tamil Nadu contributes significantly to the export efforts of our country. Exports of engineering goods, leather goods, hosiery goods and garments are very significant. The Government of Tamil Nadu has done an exemplary job in promoting the hosiery industry in Tiruppur, leather industry in North Arcot, Periyar and Chengai-MGR districts and the garment units around Madras. Tamil Nadu's contribution to easing the balance of payments crisis through exports has been of great importance. While the entire infrastructural costs for export-oriented industries have to be borne by the State, the revenue obtained through exports does not go to the State. Yet, the Centre has not provided any support for creating the infrastructure in various industrially developing areas like Tiruppur, Madurai, Ambur and Madras suburban areas. With all these handicaps, Tamil Nadu has been surging forward in the field of industrialisation. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, with a view to bringing about all-round industrialisation, has announced that an Industrial Information Centre would be set up in Delhi to guide those wanting to set up industries in Tamil Nadu. This

[Shri S. Muthu Mani]

Centre will guide the entrepreneurs and inform them of scopes and viabilities of setting up of various industries in the State. The Tamil Nadu Government has to do this because the Centre does not evince any interest in setting up industries in the State.

Sir, I have a word about small and cottage industries. Tamil Nadu has the potential for various small and cottage industries like matches poultry, prawn culture, sericulture, poultry, coir industry and so on. Though the State Government is doing its best for promoting these industries, the limitation of funds comes in the way. Therefore, I request the hon. Minister of Industry to generously sanction funds for the promotion of small and cottage industries in Tamil Nadu. As the people of the southern districts have to heavily depend on cottage industries for their survival because of scanty water and regular monsoon failure, these industries are the only ray of hope for them.

Sir, in my native village, namely Kamayagoundanpatti area and the Madurai district as a whole, grape gardens are the only source of hope. But the farmers find it dificult to harvest them and reach them to market on time. A little delay in the process will ruin them. At times they are exploited by middlemen. If coldstorage is constructed in grape-rich areas of Madurai district, these hapless farmers will be saved from this recurring loss each season. I appeal to the hon. Minister to consider this request favourably so that grapes produced are not allowed to perish bringing loss to the nation and the farmers.

I once again appeal to the Minister to look into the demands of the Tamil Nadu Government and clear them all immediately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Giri Prasad. Your time is also six minutes.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. First of all, since the Prime Minister is holding this portfolio, I think, because of his innumerable responsibilities, he is unable to concentrate on this Department. In view of his onerous responsibilities, a Cabinet Minister with independent charge for this, I think, will improve the functioning of this Ministry.

My second submission is about the industrial development in our country. I think, we are entering a third phase. In the first half of the century, according to my figures, the development was below 2 per cent. In the Plan period, may be up to the Sixth Plan or the Seventh Plan or whatever it is, average growth rate was between 5 to 6 per cent. Even in the Seventh Plan also, the growth rate was 8.5 per cent. But last year, that is in 1991-92, it was zero per cent. In 1992-93, it is 3.8 per cent. According, to the Finance Minister and other Ministers the Government hopes, perhaps, there will be a turn-around in these growth rates. But, as far as I understand, unless our country achieves between 10 to 12 per cent in industrial growth, I think we will not be able to compete on the international scene. The main drawback for this slackness during this period is the sickness in a large number of Industries. Many statistics were given here. I do not want to repeat them. But due to this sickness, more than Rs. 10,000 crores were locked up as credit from the banks which is 17 per cent of the total bank credit. This huge money, instead of being used for productive purposes, for the growth of industries, has been locked up. Not only these industries became sick, but further development of the industries also, was stopped by this. In the matter of sickness also, the small-scale sector units may be more in number but they have contributed only 26 per cent out of this blocked-up credit.

There is one sector which is very much maligned by people these days. It has become almost a fashion to malign the public sector units. Actually these public sector units along with the private sector could achieve for our country tenth place in the world in the matter of industrialisation. But more than 50 per cent of the public sector units are loss-making units. Why did they become loss-making units? There is assessment made by the Govern-

ment also. It is not due to the fault of the workers. There are a few factors which have been responsible in turning them into loss-making uits. One is the high rate of interest. Then cost and time overrun; wrong locational investment decisions, irrational product-mix, imposing marketing arrangements, wrong choice of technology, because we are getting some foreign loans, then excessive investmnets in power generation not commensurate with the network for transmission, tigth regulations in providng funds, delay in filling up top posts—many Chief Executives' posts were kept vacant—and also lack of financial and managerial autonomy, etc. Unless these things are taken care of by the Government, how can you assume the public sector units to go ahead and produce necessary results? Government's policy of sending these units, both public sector and private secotor, to the BIFR for revival or closure, I think, is not a correct method. I don't think BIFR will be able to do anything. The practice of the last 6-7 years indicates the same thing. Government, the trade unions and the management must find some solution for this. There is a tripartite mechanism. This mechanism with the help of financial institutions or banks will be able to produce immediate results, otherwise it will take 2-3-4 years and in the meantime the industry which is suffering from sickness will be just closed down which will not be helpful

Then there is the National Renewal Fund which is used to retrench people or send them on voluntary retirement. That Fund has to be used for the purpose for which it is intended. People should be trained and made productive, if not in the same industry, at least in some other sectors.

Now, foreign investment is being sought in a big way and I think the Government is begging almost everybody, political leadership and also business people and we are asking them to invest heavily in our country. But they are not coming forward because of so many reasons, both political and economic, and because of the turmoil which is taking place in our country, in spite of de-regulation and de-licensing and so many other things, including even relief in customs and excise itself. In spite of all these economic incentives, the Government is unable to attract a good number of offers from foreign sources. I think the Government also is not sincere in inviting them because the Government is trying to use this mechanism to ward off BoP crisis instead of using it for industrialisation. Our strategy for growth should not be dependent upon foreign technology or foreign investment. It should be based upon our own efforts, indigenous efforts, and our own technology because we are supposed to be the third largest country in terms of the number of technicians and scientists we have. In this background we should see that we use the right technology. The strategy for our goal should be based upon our own understanding. In this connection, I would like to point out that the Prime Minister himself had said recently that there should be a native model for our development. But in order to translate it into practice, the Government should review their policy of depending upon foreign technology or foreign investment. I think even without such help we can advance.

Another thing is, in order to make our products competitive, we must increase our productivity. I have mentioned about this earlier in the House. The productivity of our workers is less than that of the Pakistani workers. Our productivity is put at 800 dollars, whereas in the case of the Pakistani workers, it is 1400 dollars. If this is so, the Government must undertake a comprehensive study of things. If we have low interest rates and if we introduce cost-effective methods, I think we will be able to export more.

I have two last points. Now, the khadi and village industries, in adidtion to the small-scale industries, are providing a very good opportunity. Recently, there was some discussion in the meeting of the Consultative Committee on this matter. The small-scale industries pro-

[Shri N. Giri Prasad]

vide employment to 120 lakh people. The khadi and village industries, especially, the village industries, provide employment to 50 lakh people. In China also, I saw this. A number of such units are coming up, but these are tiny industries. We should see that there is a proper study in regard to these industries and utilisation of their services. We hould also provide necessary funds and new technology so that we can make use of this sector properly for the spread of industrialisation at the base level. This is one of the areas where we can provide opportunities for more employment.

My last point is about the involvement of the State Governments. This is important from the point of view of balanced development all over the country. I think the State Governments are lethargic because of two or three factors. One is finance. They do not have enough financial resources. The second is infrastructure problems. They do not have power. If they want to set up power plants, there is no coal linkage, there is no gas linkage. If they want to develop hydro power, there is no proper help from the Central Government. Wherever problems are there in developing industries at the State level, unless the Central Government comes forward with help, we will not be able to ensure balanced development of all regions. The Central Government should help the State Governments, instead of just circulating their opinion or guiding them.

Now, this sort of attitude and lack of help from the Centre is resulting in more imbalance in terms of industrial development. You heard the Members from Maharashtra and Guiarat speak. These are the only two industrially developed States, at least in relation to the Indian conditions. But there are several States which are on the other extreme. Take, for example, the States in the North east and Bihar. There are other States in between. Therefore, the Government must have a proper strategy for development of the States in the North east in spite of their conditions and in spite of the local problems there. What about Bihar? There may be a non-Congress Government there. That should not stand in the way. Industry is in the Condurrent List. Therefore, I think the Central Government should have a serious look into these problems and see that there is a balanced industrial development.

In the end, I would say that if we want to industrialise our country, we must change our policy. On the other hand, if you continue with your policy like this, we will become lethargic and it will result in deindustrialisation. Already deindustrialisation has set in. Unless it is reversed, our country will not go forward. Otherwise, it will become a very backward country in addition to the other problems which are already there. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, the hon. Minister in charge of small-scale industries, Mr. Arunachalam, will reply.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, let the hon. Minister reply tomorrow. Tomorrow, we have no Private Members' Business. Therefore, the reply can be there tomorrow. I think it was agreed.

10.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Mohanty, some Members wanted to hear the reply. Let them hear it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): Sir,...

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): Is he intervening?

SHRI M. ARUNACHALAM: I am replying relating to small scale sector.

Sir, I would like to thank all the hon. Members who have participated in the discussion. I would like to answer with regard to the small scale sector only. Before coming to the specific issues, I would like to highlight the performance of the small scale sector over the years. If you see the performance of the small scale sector for the past 18 years, the total number of units, both registered and un-registered, has increased from 4.1 lakh in 1973-74 to 21 lakh units in 1991-92. Coming to the production at current prices, products worth Rs. 7,200 crores were manufactured in 1973-74. Now the production has gone up to the extent of Rs. 1,78,699 crores.

As far as employment opportunities in this sector are concerned, the number in the year 1973 was 39.7 lakh and now it has gone up to 130 lakh.

Coming to the growth rate in the manufacturing sector in small scale, taking the general index of industrial production during the last three years, during 1990-91 the growth rate of production was 8.5 per cent while the growth in the total industrial production was 8.3 per cent. In 1991-92 the growth rate was 2.4 per cent whereas the general growth rate was minus 0.1 per cent. This year 1992-93 the growth rate is 5.2 per cent and the general growth rate is 3.8 per cent. If you see the growth rate in small scale sector, it has always been higher than the growth in the total manufacturing sector. The growth rate which was to be of the order of 8.5 per cent in 1981 discreased to 2.4 per cent during 1991-92. The negative growth rate was withnessed in the whole manufacturing sector during 1991-92 on account of various adverse factors, such as credit squeeze, foreign exchange constraints, demand recession, etc.

Coming to the issues raised by hon. Shri T.N. Chaturvedi, he has mentioned about the sickness in the small scale sector. The latest figures about sick units in the small scale sector are available. According to the Reserve Bank of India as on 31st March, 1991, there are about 21 lakh sick units. They are sick as per the definition of the Reserve Bank of India. This amounts to about 10 per cent of the total number of units in the small scale sector. The Government is taking a lot of measures to rehabilitate the sick units. Some of them are as under.

The Reserve Bank has set up a State level Inter-institutional committees in each State for working out rehabilitation package in consultation with the financial institutions, banks and the State Governments.

The Reserve Bank of India has issued detailed guidelines to commercial banks with reference to the parameters of sickness, viability norms, relief to be considered, etc. Sir, number three, a committee was appointed to look into the credit needs and the sickness of the small-scale sector. That is headed by Mr. Naik, ex-Deputy Governor of the Reserve Bank. As the House is aware, the committee has made its recommendations to the Reserve Bank. Some of the recommendations have been accepted, and other things are under the consideration of the Reserve Bank of India.

The hon. Member, Mr. Chaturvedi, has also mentioned that the closed units range between 30 and 40 per cent in 1987-88. This information on closure is not for one year but for the 15-year period since the First Census. The major reasons for closure are that about 40 per cent of the units are closed for financial problems, and 15 per cent of the units are closed for marketing problems. Other reasons for closure are legal problems, dispute among the owners, management problems and diversion of funds by partners or owners. Sir, all the SSI units are in the private sector. As you are all aware, no individual person or no single factor can be held responsible for such closures.

Coming to the hon. Member, Shri Jadhav he has mentioned that 99 per cent of the sick units are in the small-scale sector. That is correct, Sir. If you see the figures, the total number of sick

[Shri M. Arunachalam]

units in the small-scale sector is 2,21,472. That is 99 per cent of the total sick Units. The outstanding dues from these closed units are 25 per cent of the total credit given to the industrial area. About the non-SSI sector, the sick units are about 1,461, and weak units are 876. That comprises about 75 per cent of the total credit. Therefore, it is not an alarming figure.

Sir, he has mentioned about the need for finance to the SSI sector. A number of other Members have also mentioned about the credit flow to the small-scale sector. The Reserve Bank of India committee, about which I have just now mentioned, i.e. the Naik Committee, set up in December, 1991 after the new policy announcement, has gone into the problems in detail. It has looked into the institutional credit needs of the small-scale sector. The Committee has recommended for meeting about 20 per cent of the output by way of working capital against 8 to 9 per cent at present. The RBI has advised banks to give preference to small-scale industrial units for credit flow through an annual credit plan.

Sir, Mr. Jadhav has mentioned about small village-industries and about the potential of the employment opportunities in this sector. Mr. Prasad has mentioned that the Khadi and Village Industries Commission is providing employment opportunities to about 50 lakh persons. We are reviewing the working of the KVIC. The Prime Minister himself has taken keen interest, and he is likely to announce a committee headed by himself to review the working of the Khadi and Village Industries Commission. That shows that Government is very keen to promote village and rural industries through the KVIC.

Sir, Shri Jadhav mentioned about the need for continuous monitoring and support of technology, marketing, finance etc. So far as rural industries are concerned, Government has already taken steps to provide finance, improve technology and promote marketing of their products. The Khadi and Village Industries Commission has signed a memorandum of association with the CSIR for improving the technology for rural industries. An in-house research by Khadi and Village Industries Commission has been set up. Interest subsidy has been provided by KVIC both to Khadi and Village Industries Marketing of the village industries products are being done through the sales outlets of the Khadi and Village Industries Commission.

Shrimati Kamla Sinha has mentioned about the technical support for the rural industries. Just now I have mentioned what we are doing.

Shri V. Narayanasamy has raised certain points about the NSIC. NSIC is doing the technology development work. We cannot deny that we are even transferring our technology to the developing countries. I have even visited some of the developing countries. There our NSIC is playing a vital role in the technology transfer. Shri V. Narayanasamy has also mentioned about the need for developing agro-based technology and that the import of technology should be welcome for these industries. As I have mentioned during the last year, i.e. 1991-92, the KVIC has given employment opportunities to fifty lakh persons. As I said, to improve the effectiveness of the Khadi and Village Industries Commission, the Prime Minister is very shortly going to constitute a Committee under his Chairmanship. Shri Narayanasamy has also mentioned about the capital needs of the small-scale sector. As I said, the Reserve Bank of India has issued guidelines to the banks on 7th April, 1993 asking that the working capital limits can be computed on the basis of the 30 per cent of the SSI projections in the turn-over. The banks should set up credit flows for the SSIs during the 8th Plan period and that they should draw up annual credit budgets. An effective grievances redressel machinery within each bank should be set up. The banks should strictly the follow time-frame laid down and the procedures for the disposal of loan applications.

Mr. Patel raised a few issues. One point he raised was about the mini-growth centres. It is in the pipeline. My Department is working out the modalities of developing mini-growth centres in various parts of the country. He has also said that the agro-based industries should be given adequate support. Of course, we are doing it but if there are more suggestions they are welcome.

Shri Ganesan raised a lot of points about the large-scale industries. My colleague will be answering those points.

Shri Muthu Mani has said that the Government of India is not giving due encouragement to the industries I would like to inform him that in the Khadi-and Village Industries sector, Tamil Nadu is playing a vital role and they are getting a major share from the Commission. I would request the hon. Member since Chief Minister is holding the industries portfolio, they can have better interaction with the Government of India. I find that there is no no interaction at all with the Government of India departments.

With these words I once again thank the Members who

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उद्योग मंत्रालय के कार्यों में अपनी अभिरूचि दिखाई है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं।

सभी मिला कर नौ माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। हम उनके प्रति बार-बार आभार व्यक्त करते हैं। जो उनकी चिंता है, वह हमारी भी चिंता है।

अभी सब से पहले मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं चतुर्वेदीजी का, कमला सिन्हा जी का, जिन्होंने अपनी आंखों पर ऐसा एनक चढ़ाया है कि हमारी भारत सरकार की उद्योग नीति, आर्थिक नीति, सभी जो प्रगति के रास्ते पर हमारे देश को ले जा रहे हैं...उन्हें अंधेरा ही अंधेरा सभी जगह दिख रहा है। अंधेरा ही पक्ष देखता है और इतने वह फ्रस्ट्रेटड हैं कि आज पहली बार मुझे ऐसा देखने को मौका लग रहा है कि जो जिन्होंने हमारी डिबेट को ओपन किया है वह उत्तर भी सुनने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके और सदन के ऊपर यह निर्भर करता है सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि कितनी गंभीरता से वह देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक नीति के ऊपर उनका क्या मनन हो रहा है, क्या चिंतन हो रहा है, यह आप सब के ऊपर है कि उत्तर भी सुनने के लिए वह यहां विद्यमान नहीं हैं। मैं सभी बिंदुओं पर अलग-अलग करके अभी उत्तर नहीं देना चाहती हूं, क्योंकि काफी समय बीत गया है। अनेक विभागों के ऊपर भी चर्चा हुई है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग... (व्यवधान)

SHRI MISA R. GANESAN: Honourable Members from the Treasury Benches are also not here.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: That is a different thing. But you must realise that the opener of the debate is not here even to listen to the answer of the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Some of the Members are here.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...सौ सुनार का और एक लौहार का। तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही थी कि चतुर्वेदी जी ने यह कहा कि हमारी जो नई औद्योगिक नीति है वह टैक्नोलोजी के नाम पर जालसाजी कर रही है। उन्होंने यह कहा कि हमारी औद्योगिक नीति मजाक बन गई है। मजाक तो उन्होंने बनाया जो आपके सामने है। नई औद्यो-

[श्रीमती कृष्णा साही]

गिक नीति के बाद प्रायः दो वर्ष हमारे बीत हैं, 1980 के दशक में जो सुधार लाए जा रहे थे और जिनके चलते औद्योगिक विकास में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उनको नई नीति के द्वारा और आगे बढ़ाने की कार्यवाही की गई है। आंकड़ों को बहुत प्रस्तुत किया गया है कुछ समाचार-पत्रों की चर्चा की गई, विभिन्न सी० ए० जी० रिपोर्ट की चर्चा की गई। तो समाचार-पत्रों को पढ़ने के बाद जो उनको मालूम है या जो हम लोग भी पढ़ कर जानते हैं, उसमें हकीकत से वह कहीं और भी बात है, यह मैं नहीं कहती कि सारी बातें समाचार-पत्रों में गलत ही छपती हैं, सही गलत सब होती हैं, लेकिन अभी बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन थोड़ा मैं भी बताना चाहती हूं, उन्होंने कहा कि हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। नई औद्योगिक नीति जो हमने अपनायी है वह दिशा-भ्रमित है, लोगों को भ्रमित कर रही है। मैं सम्मान सहित बताना चाहती हूं कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण है और औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाना, भारतीय उद्योग में टैक्नोलोजी उन्नत करना, उत्पादकता, गुणवत्ता तथा कंपीटीटिवनैस में सुधार ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कंपीट कर सकें। कमला सिन्हा जी ने कहा कि हम अपनी परंपरा से हट गए, तो अब बैलगाड़ी पर वह पटना क्यों नहीं जातीं? हवाई जहाज पर पटना जाना चाहती हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो युग है, जो अभी आर्थिक परिवर्तन हो रहा है सारे विश्व के स्तर पर तो हम उससे अगर अलग रहेंगे तो हम कहां जायेंगे? हम तो बहुत साल पीछे चले जायेंगे। इसलिए किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में जो हमारी नई औद्योगिक नीति है वह देश में आर्थिक प्रगति की ओर हमें निस्संदेह ले जा रही है और ले जाएगी। औद्योगिक दर की बात की गई थी। भारत की आर्थिक स्थिति 1991 में बहुत ही कठिन हो गई थी। विदेशी ऋण का अत्यधिक भार हो गया था एवं विदेशी मुद्रा कोष प्रायः समाप्त सा हो गया था। अतः उस समय अनेक कड़े कदम उठाने पड़े थे सरकार को जिनके चलते 1991 और 1992 में औद्योगिक प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ा था और वार्षिक दर माइनस 0.1 हो गई। स्थिति के संभलने के बाद उपयुक्त उपाय किए गए। जिनके फलस्वरूप अप्रैल से दिसंबर, 1992 में औद्योगिक विकास दर 3.6 प्रतिशत हुई। यह पर्याप्त नहीं है, परन्तु पूर्व वर्ष की तुलना में अवश्य ही अच्छी कही जाएगी। नयी नीति की चतुर्वेदी जी को बहुत चिंता थी। उन्होंने कहा कि यह क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि क्रांतिकारी कदम उठाने का अवसर गैर-कांग्रेसी सरकारों को भी मिला था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला तो 15-16 महीनों तक वह जिस सरकार का सहयोग कर रहे थे, उन्होंने उन 15-16 महीनों में ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए कि जनता ने उनको रफा दफा कर दिया। महोदय, जहां तक नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव का प्रश्न है, मात्र 20-22 माह में इसका मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा, फिर भी कुछ उत्साहवर्धक आंकड़े आए हैं। महोदय, यह कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि रातभर में सब हो जाएगा। कोई भी नई नीति आती है तो उसके कार्यान्वयन से लेकर प्रगति तक एक नया फेज आता है और उसमें समय लगता है। तो नई नीति के बाद औद्योगिक अनुमोदनों में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विदेशी टैक्नोलोजी समझौतों में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पूंजी निवेश के अनुमोदनों की रकम में लगभग 20 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 के बजट से औद्योगिक विकास की दर अवश्य ही और बढ़ेगी, ऐसी आशा की जा सकती है। महोदय, न केवल पूंजी निवेश तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति होगी बल्कि भारतीय उद्योग अपनी कैपेबिलिटी, दक्षता और कॉस्ट इफक्टिवनेस

भी बनाएगी। महोदय, अब अधिकतर उद्योग लायसेंस से मुक्त कर दिए हैं और ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए नई नीति के बाद अगस्त, 91 से अप्रैल, 93 तक लगभग 9200 औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन फाइल हुए हैं। इन परियोजनाओं को साकार रूप देने में दो-तीन साल तो लगेंगे। उसके बाद उत्पादन एवं नियोजन में काफी वृद्धि की आशा की जाती है और हम सोचते हैं कि इसमें हमारी प्रगति होगी ही।

महोदय, यहां फॉरेन इनवेस्टमेंट या विदेशी निवेश की चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने विदेशी पूंजी निवेश का मुद्दा उठाया है। महोदय, नई औद्योगिक नीति 1991 में अन्य महत्वपूर्ण बातों के साथ ही विदेशी पूंजी निवेश पर भी काफी बल दिया गया है क्योंकि उससे टैक्नोलोजी ट्रांसफर, मार्केटिंग एक्सपर्टीज, आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी तथा निर्यात संवर्धन का लाभ मिलने वाला है। भारत के आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों में अभिरुचि बढ़ी है और उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हुआ है। निवेश के प्रस्तावों में जहां 1990 में मात्र 125 करोड़, रुपए का विदेशी निवेश निहित था, वहां 1992 में प्रायः 3900 करोड़ रुपए हो गया और मार्च 1993 तक लगभग 2600 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं। इन प्रस्तावित निवेशों के 90 प्रतिशत नई नीति के परिशिष्ट–3 के उच्च प्राथमिकता वाले सेक्टर्स में हैं मतलब प्रायरिटी सेक्टर्ज में है जोकि संतोष का विषय है महोदय, सबसे अधिक प्रस्ताव तेल शोधन, ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, कैमकल्स, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक इक्युपमेंट्स एवं इंडस्ट्रियल मशीनरी के क्षेत्र में ।

महोदय, यह भी चर्चा चली कि हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। विदेशी सामान आएगा तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। आर्थिक गुलामी तो तब होंगी जब हम आगे प्रगति नहीं करेंगे। जो इस नीति पर भारत की स्वाधीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है एवं यह कहना गलत है कि देश मल्टी-नेशनल्स के हाथों में बेचा जा रहा है। पेप्सी, कोका-कोला की भी चर्चा चली थी। तो ये जो उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों का उदाहरण दिया जाता है, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी कंपनियों के प्रस्तावों को दिया गया अनुमोदन कुल अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों का बहुत ही छोटा अंश है, बहुत छोटा अंश है और 90 प्रतिशत जो भी अनुमोदन हुए हैं वह तो प्रायरिटी सेक्टर्स के लिए हैं। साथ ही ऐसी विख्यात कंपनियों के इस देश में प्रवेश से अन्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी वातावरण बनाना है तभी तो भारतीय अर्थ व्यवस्था में विदेशी निवेशकों का उत्साह बढ़ेगा। हमारी ओर तभी झुकेंगे। इसके अलावा इनके प्रवेश से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी कंपटीशन होगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता, लागत पर नियंत्रण, डिजायन में सुधार, गुणवत्ता में वृद्धि तथा आफ्टर सेल सर्विस में सुधार होता है। लेकिन, लाभ अंततः उपभोक्ताओं को होगा। किसी माननीय सदस्य ने ओब्सोलीट टेक्नोलोजी की भी कुछ चर्चा की थी। इसकी आलोचना की गई है, लेकिन हम तो इतना ही कह सकते हैं कि अभी भारतीय उद्योग इतना कमजोर नहीं है कि ओबसोलीट टेक्नोलोजी का वह सामना नहीं कर सकेगा। वह बहुत अच्छी तरह से सामना कर सकेगा।

महोदय, एशियाई देशों में चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया और ताइवान में भारत की तुलना में काफी अधिक पूंजी निवेश हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उन देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों का उदारीकरण और सुधार बहुत पहले ही आरंभ कर दिया था ताकि उनके देश में पूंजी निवेश आकर्षित हो सके। आजाद बाद में हुए। उन्होंने जो नई आर्थिक नीति अपनाई, जो औद्योगिक नीति अपनाई, उसके कारण तकी प्रगति हुई। उदाहरण स्वरूप ची ने 1979, इंडोनेशिया ने 1983 तथा सिंगापुर

[श्रीमती कृष्णा साही]

और मेलेशिया ने उससे भी पूर्व उदारीकरण नीति को अपनाया था। इसके अलावा उनके यहां आयात, निर्यात शूल्क भी भारत की तुलना में बहुत ही कम है। हमारी सरकार ने उदारीकरण की व्यापक नीति मात्र दो वर्ष पहले प्रारंभ की है। अभी 1993–94 के बजट में शुल्क और करों में बहुत ही अधिक मात्रा में राहत दी गई है। अन्य विकासशील देशों के स्तर पर पहुंचने में तो हमें समय लगेगा, परन्तु तेजी के साथ कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि जल्दी ही उन देशों के बराबर आ जाएंगे। अमरीका के बाद भारत में ही सबसे अधिक प्रशिक्षित और कुशल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, मेनपावर हमारे यहां ज्यादा है, टेक्नीशियन्स हमारे यहां उपलब्ध हैं। इनको मुक्त वातावरण मिलेगा और अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। इस तरह वह विदेशों में भी कंपटीशन में आ सकते हैं और हमारे देश का नाम वह रोशन करेंगे।

सरकारी क्षेत्रों की भी चर्चा की गई है। सरकारी क्षेत्र हमारे देश के विकास की स्ट्रेटजी का अभिन्न अंग है। लोक क्षेत्र उद्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें दो मत नहीं हो सकते। इससे हम भी सहमत हैं कि समस्या और उत्पन्न होगी, जिसके कारण कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कम उत्पादन हो रहा है। हमारी टेक्नोलोजी भी कुछ पुरानी हो गई है। इससे लगातार हानि हो रही है। उसी पुरानी टेक्नोलोजी को तो हम नया करना चाहते हैं। और, वह कहते हैं कि बाहर के लोग आकर के हमारे देश को ही समाप्त कर देंगे, हम फिर से गुलामी की ओर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी नई नीति में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है और सरकारी उद्यमों के लिए मात्र आठ ही उद्योग हैं, जो कि आरक्षित रखे गए हैं लेकिन लोक उद्यम को और भी दक्ष और कंपिटिटिव बनाने की ओर कार्यवाही की जा रही है।

महोदय, वित्तीय संसाधन की कुछ कमी है। अब यह बहुत अनिश्चित काल तक इस तरह की परिस्थिति में रहना कोई ठीक नहीं हो होगा, इसलिए सरकार सभी सिक यूनिट को राजसहायता उस हद तक नहीं दे सकती है क्योंकि हमारी भी कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं। तो रूग्ण इकाइयों को रिस्ट्रक्चरिंग करना है और रिहेबलिटेशन के लिए बी०आई० एफ०आर० को रेफर किया गया है, और आगे भी करेंगे। उनको और अधिक हम स्वायतता देना चाहते हैं। ... (व्यवधान) ... एकाउन्टेबिलिटि भी उनकी होगी। मेमोरडम आफ अंडरस्टेंडिंग के माध्यम से वह सरकार से समझौते करते है कि उन्हें क्या काम करना है, किन मानदंडों के अनुसार उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। नई नीति में यह व्यवस्था है। यह कहा गया है कि हमारे उपक्रम के कर्मचारियों के ऊपर बूरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसी आशंका नहीं होना चाहिए। ... यह मैं दोहराना चाहती हूं कि सरकार वचनबद्ध है, कमिटेड है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा पूर्ण रूप से की जाएगी। नेशनल रेन्यूअल फंड के माध्यम से वालेंटरी रिटायरमेंट स्कीम तथा री ट्रेनिंग और री एम्प्लायमेंट के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

पब्लिक सैक्टर डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात चली थी। नई नीति में लोक-क्षेत्र के संबंध में प्रावधानों की चर्चा मैंने पहले भी थोड़ी सी की है, चतुर्वेदी जी ने जो बात कही थी डिसइन्वेस्टमेंट की, तो उसे दोहराना नहीं चाहती हूं क्योंकि पी०ए०सी० की चर्चा मैंने कर दी है। सिर्फ पब्लिक सक्टर युनिट्स की बात है, इन्हें बी०आई० एफ०आर० को रेफर किया गया है, लेकिन उपयुक्त पैकेज डैयार होने पर सरकार के द्वारा, एक-एक, केस टु केस, हर केस की मैरिट को देखा जाएगा और उसके आधार पर

लोकहित में जो आवश्यक निर्णय है, वही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी इकाई को वॉयबल बनाया जा सकता है, इसके लिए स्ट्रक्चरिंग और रेनोवेशन के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो भी उसको आवश्यक सहायता चाहिए, जो भी उसको सपोर्ट चाहिए, वह दिया जाएगा। यदि वर्कर्स कोआपरेटिव कोई वॉयबल योजना के साथ सामने आते हैं तो हम अवश्य उनका सहयोग करेंगे।

एच०ई०सी० की ओर भेल की चर्चा हुई। एच०ई०सी० के पास पर्याप्त आर्डर है और एच०ई०सी० को टर्न एराउंड करने के लिए सरकार एवं बैंकों द्वारा सहायता दी जा रही है। भेल की चर्चा हुई, तो वहां पर सरकार उनको संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मदद की जा रही है, सरकार और बैंक के द्वारा भी सहायता दी जा रही है और भेल का निर्यात 1989–90 में 381 करोड़ था जो बढ़कर 1992–93 में 786 करोड़ हुआ है। इसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए की भेल का जो निर्यात हुआ है 1989–90 के 381 करोड़ से बढ़कर 1992–93 में 786 करोड़ रुपए हुआ है और इसे और भी बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है।

बार-बार राज्यों की चर्चा की गई है। हमारे कुलीग ने कहा ही है –मुथु मणि जी ने जब कहा कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं कहना चाहती हूं कि औद्योगिक विकास में राज्यों की एक अपनी अलग भूमिका है। तो इंटर एक्शन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं; हमने नई औद्योगिक नीति बनाई और उसके आलोक में तथा उसको सहयोग करते हुए जो भी प्राप्त हमारे साथ सहयोग करेंगे, हमारा मार्गदर्शन चाहेंगे, तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कमला सिन्हा जी ने कहा कि 1952 में, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहती थी, वे हैं भी नहीं लेकिन मैं जब बोल रही हूं तो वह प्रोसिडिंग में उन तक पहुंच ही जाएगा। तो 1952 की चर्चा की थी, वो बिल नहीं था गवर्नमेंट का कुछ काम करने का, तो उसका अभाव था। तो मैं तो कहूंगी कि 1952 जो था, वह बिहार के लिए गोल्डन ऐज था वे शायद भूल गई होंगी कि उसी समय पोलिटिकल बिल के कारण ही वहां जो रिफाइनरीज हैं, जो फर्टिलाइजर के कारखाने हैं जो सिंदरी देख रहे हैं, जो बोकारो देख रहे हैं, हटिया देख रहे हैं, यह सब उसी युग की इस देश को देन है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 1967, 1987 और 1989, मौका दिया गया सभी राज्यों को भी और यहां भी मौका दिया गया गैर कांग्रेसी सरकारों को, तो जो चमत्कार हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं कि राज्य के औद्योगिकीकरण तथा उसके संतुलित विकास का उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर है। तो अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं हुआ और विकास और प्रक्रियाओं का सरलीकरण नहीं करेंगे, उद्यमी सेवा प्रकोष्ट नहीं बनाएंगे, मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, यह सब जब तक वे सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम उसमें किसी प्रकार की उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगी कि ग्रोथ सेंटर्स की जो भारत सरकार की योजना है मैं उस पर बाद में दो मिनट कहूंगी, लेकिन अभी यही कहना चाहती हूं कि ग्रोथ सेंटर्स राज्यों के विकास के लिए है लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा न हमें उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, न समय पर वहां से कोई जवाब आता है, तो फिर हमारी भी लाचारी हो जाती है। तो कुछ राज्यों में आई० ई०एम० की बात उठाई गई थी। उदारीकरण व्यवस्था में उद्यमी को स्वयं अपने विवेक का उपयोग करके, अपनी कमर्शियल जजमेंट के आधार पर उद्योग और स्थान के बारे में उसको निर्णय लेना है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वे भी अपने-अपने राज्यों में जहां से वे आते हैं, उनको प्रभावित करें, सरकारों को बनाएं ताकि उनकी सरकारें अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और वातावरण को उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल बनाएं और फ्रेंडली वातावरण बनाएं, ताकि लोग वहां आ सकें।

बेरोजगारी की भी चर्चा की गई है। माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की है, वह हमारी भी चिन्ता है। इसे हम बहुत ही अधिक

[श्रीमती कृष्णा साही]

एप्रिसिएट करते हैं । एन०डी०सी० की एक उप-समिति ने इस पर अध्ययन किया है और पुनः कल ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में घोषणा की है कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में एन०डी०सी० की बैठक बुलाई जाएगी और इस प्रस्ताव पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा । उत्तर पूर्वी राज्यों के औद्योगिक विकास की हमारी योजना है । जो पिछड़े इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों एवं हिमाचल प्रदेश इत्यादि जैसे पिछड़े इलाकों की मुख्य समस्या परिवहन समस्या है । तो इन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा उत्पादों की ढुलाई में उन्हें अधिक खर्च वहन करना पड़ता है । अतः ऐसे क्षेत्रों के लिए पहले से ही परिवहन अनुदान योजना चलाई जा रही है । ढुलाई के खर्च पर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान एवं हिमाचल के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । प्रारम्भ से 104.55 करोड़ रुपए राज्यों को रि-एम्बर्स किए जा चुके हैं । 1993–94 के बजट में उत्तर पूर्वी राज्यों—जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और विभिन्न यूनियन टेरिटोरीज में नए उद्योग लगाने के लिए 5 वर्ष का टैक्स होलीडे भी दिया गया है । उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम सरकार एवं आई०बी०पी० का जोइंट वेंचर रिफाइनरी प्रोजेक्ट बन रहा है, गैस क्रेकर प्रोजेक्ट को भी अनुमोदित किया गया है । मेघालय में सीमेंट प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है और इसी प्रकार भारत सरकार ने ग्रोथ सेंटर योजना को भी रखा है, जिसमें औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विकास योजना प्रारम्भ की गई है । प्रत्येक केन्द्र के लिए 30 करोड़ रुपये की योजना बनाई जाएगी, जिससे लगभग 400 से 800 हेक्टेयर में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । विद्युत, पानी, दूरसंचार, सड़क, बैंक इत्यादि की व्यवस्था से आकर्षित होकर उद्योग स्वयं वहाँ जाना चाहेंगे, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वैसा होगा । तो इस तरह से 30 करोड़ रुपये में से केन्द्र सरकार को दस करोड़ रुपए देने हैं, बाकी राज्य सरकार दे, वित्तीय संस्थान दे, मार्केट बोरोइंग से प्राप्त किया जाए और यह जो योजनाएं हैं, जितनी जल्दी राज्य सरकारें सहयोग करके अपनी योजनाओं को हमारे पास स्वीकृति के लिए भेजेंगी, उतनी जल्दी हम इसमें काम करेंगे । विभिन्न मंत्रालयों के सम्बन्ध में, माननीय सदस्यों ने जो विचार दिए हैं, उनको सम्बन्धित मंत्रालयों में मंत्री महोदय के पास पहुंचा दिया जाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद देती हूं और आभार व्यक्त करती हूं ।

SHRI S. MUTHU MANI: Sir, may I ask one question? May I know from the Minister, what is the concrete proposal of the Central Government to protect the employment of the workers who are retrenched due to modernisation of industries?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister has already explained the position.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: It does not come under my Department.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister has replied to all the points raised by the Members.

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Sir, the Minister in her speech has said that the Centre is willing to cooperate with the State Governments, particularly the non-Congress Governments for the development of industries. She has also said that the non-Congress Government are not willing to come forward to take help from the Centre. If both are true, what will be the fate of our industries?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister has said, "Some of the State Governments." Now, the discussion on the working of the Ministry of Industry is over. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at forty minutes past ten of the clock till eleven of the clock on Friday, the 14th May, 1993.